हिन्दी दैनिक

लखनऊ जंक्शन

RNI NO.-UPHIN/2015/64743 Email-lkojunction@gmail.com

वर्षः 11 अंकः 131 लखनऊ, बुधवार 31 दिसम्बर 2025 पृष्ठः 04 मूल्यः 01 रूपये

रक्षा मंत्रालय ने 4,666 करोड़ रुपये सैन्य सौदों पर लगाई मुहर

सेना-नौसेना को मिलेंगे ये अहम हथियार

दिल्ली ब्यूरो

नई दिल्ली। रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को क्लोज क्वार्टर बैटल (सीक्यूबी) कार्बाइन और हैवी वेट टॉरपीडो की खरीद के लिए कुल 4,666 करोड़ रुपये की लागत के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। मंत्रालय ने बताया कि भारत फोर्ज लिमिटेड और पीएलआर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ 2,770 करोड़ रुपये की युद्धक कार्बाइन और सहायक उपकरणों के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। सेना और नौसेना को मिलेगी क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन भारतीय सेना और नौसेना के लिए 4.25 लाख से अधिक क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन और उससे जुड़े उपकरण खरीदे जाएंगे। इसके

लिए करीब 2,770 करोड़ रुपये का अनुबंध भारत फोर्ज लिमिटेड और पीएलआर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ किया गया है। यह कार्बाइन पुराने हथियारों की जगह लेगी और सैनिकों को नजदीकी मुकाबले में ज्यादा सटीक और तेज मारक क्षमता देगी। हल्की और कॉम्पैक्ट होने के कारण यह सीमित जगहों में भी प्रभावी साबित होगी। समुद्र में भी बढ़ेगी ताकत वहीं, भारतीय नौसेना की कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों के लिए 48 भारी वजन वाले टॉरपीडो खरीदने का भी फैसला लिया गया है। इसके लिए इटली की कंपनी डब्ल्यूएएसएस सबमरीन सिस्टम्स के साथ करीब 1,896 करोड़ रुपये का अनुबंध किया गया है। इन टॉरपीडो की आपूर्ति अप्रैल 2028 से शुरू होगी और 2030 की शुरुआत तक पूरी हो जाएगी। इससे नौसेना की छह पनडुब्बियों की युद्ध क्षमता और मजबूत होगी। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025–26 में अब तक सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए 1.82 लाख करोड़ रुपये से अधिक के पूंजीगत अनुबंध किए जा चुके हैं। यह कदम सेना और नौसेना को आधुनिक, मजबूत और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने की दिशा में बड़ा प्रयास माना जा रहा है।

योगी कैबिनेट का जल्द होगा विस्तार, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने सीएम आवास पर की मैराथान बैठक; दिल्ली रवाना

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। प्रदेश में भाजपा के नए अध्यक्ष की तैनाती के बाद अब सरकार और संगठन में बदलाव की कवाययद तेज हो गई है। इसी कड़ी में मंगलवार को मुख्यमंत्री की मौजूदगी में उनके आवास पर कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही संगठन में बदलाव पर भी चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक करीब एक सवा घंटे से अधिक देर चली बैठक में प्रस्तावित विस्तार के स्वरूप की रूपरेखा पर चर्चा हुई और लगभग कोर कमेटी की सहमति भी बन गई है। माना जा रहा है कि दिल्ली से हरी झंडी मिलते ही कभी भी विस्तार पर अमल किया जा सकता है। इसके बाद संगठन के पुर्नगठन का काम शुरू होगा |मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को पूरे दिन लखनऊ में थे और उनका पूरा समय आरक्षित था। देर शाम को उनके आवास पर प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, महामंत्री

संगठन धर्मपाल सिंह, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के अलावा संघ से क्षेत्र प्रचारक अनिल कुमार व अन्य संघ के पदाधिकारी पहुंचे। सभी लोग करीब सीएम आवास पर सवा घंटे अधिक समय तक रहे। भूपेंद्र चौधरी बनाए जा सकते हैं मंत्री सूत्रों का कहना है कि सीएम की मौजूदगी में हुई बैठक में सबसे अधिक चर्चा मंत्रिमंडल विस्तार पर हुई। भरोसेमंद सूत्रों का कहना है कि निर्वतमान प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत करीब आधे दर्जन विधायकों को मंत्री बनाए जाने पर गंभीरता से विचार किया गया। जिसमें 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए जातीय समीकरण पर विशेष ध्यान दिए जाने के भी सुझाव दिए गए हैं। इसी फार्मूले पर भाजपा के प्रदेश संगठन का भी पुर्नगठन करने पर सहमति बनी है। प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली रवाना बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी देर रात दिल्ली रवाना हो गए हैं। वहीं, बुधवार को कोर कमेटी से जुड़े कुछ और नेता भी दिल्ली जा सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि पंकज चौधरी दिल्ली में हाईकमान के सामने कोर कमेटी की बैठक में हुई चर्चा और प्रस्ताव की जानकारी देंगे। इसके बाद मंत्रिमंडल के विस्तार पर अंतिम फैसला लिया जाएगा।

संक्षिप्त समाचार

राहुल गांधी ने खालिदा जिया के निधन पर जताया दुख, बोले-बीएनपी चेयरपर्सन ने बांग्लादेश की राजनीतिक यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई

एजेंसी

नयी दिल्ली। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की चेयरपर्सन बेगम खालिदा जिया का मंगलवार सुबह निधन हो गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उनके निधन पर गहरा दुख जताया और उनके परिवार, समर्थकों और बांग्लादेश के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के निधन से दुखी हूं। सार्वजनिक जीवन में अपने लंबे करियर के दौरान, उन्होंने बांग्लादेश की राजनीतिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके परिवार, समर्थकों और बांग्लादेश के लोगों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं।वहीं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी खालिदा जिया के निधन पर शोक जताया। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा, इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से, मैं बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में, उन्होंने देश की राजनीतिक यात्रा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके परिवार, समर्थकों और बांग्लादेश के लोगों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं।

पीएम मोदी ने नेताजी को किया याद, 1943 में पोर्ट ब्लेयर में पहली बार फहराया था तिरंगा

एजेंसी

नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 1943 में आज ही के दिन पोर्ट ब्लेयर में तिरंगा फहराने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद किया। पीएम मोदी ने कहा कि वह क्षण सभी को याद दिलाता है कि स्वतंत्रता केवल आकांक्षा से नहीं, बल्कि सामर्थ्य, परिश्रम, न्याय और संगठित संकल्प से आकार लेती है। आजाद हिंद फौज या 'इंडियन नेशनल आर्मी' के प्रमुख बोस ने 30 दिसंबर 1943 को पोर्ट ब्लेयर में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। मोदी ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "आज ही के दिन 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अदम्य साहस और वीरता के साथ पोर्ट ब्लेयर में तिरंगा फहराया था। वह क्षण हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता केवल आकांक्षा से नहीं, बल्कि सामर्थ्य, परिश्रम, न्याय और संगठित संकल्प से आकार लेती है।"

लखनऊ में 19 जनवरी से होगा देशभर के विधानसभा अध्यक्षों का सम्मेलन, महाना बोले- तीन दिन चलेगा आयोजन

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने बताया कि लखनऊ में 19 से 21 जनवरी तक देश की सभी विधानसभा एवं विधान परिषदों के अध्यक्षों और सभापतियों का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 31 विधानसभा अध्यक्ष तथा छह राज्यों– आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश की विधान परिषदों के सभापति भाग लेंगे। विधानभवन में आयोजित प्रेस वार्ता में सतीश महाना ने बताया कि तीन दिन चलने वाले इस सम्मेलन का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला करेंगे, जबकि 21 जनवरी को समापन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल करेंगी। सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। 22 जनवरी को सभी पीठासीन

अधिकारियों को अयोध्या भ्रमण कराया जाएगा।

इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने हाल ही में संपन्न शीतकालीन सत्र की उपलब्धियां भी साझा कीं। उन्होंने बताया कि 19 से 24 दिसंबर तक चले विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन की कार्यवाही एक बार भी स्थगित नहीं हुई और सभी निर्धारित विधायी कार्य पूरे किए गए। इस अवधि में सदन की कुल कार्यवाही 24 घंटे 50 मिनट तक चली। महाना ने बताया कि सत्र के दौरान कुल 2776 प्रश्न प्राप्त हुए, जिनमें अल्पसूचित तारांकित प्रश्न 1, तारांकित प्रश्न 451 और अतारांकित प्रश्न 1842 रहे। कुल प्राप्त प्रश्नों में से 2650 प्रश्न (95.46 प्रतिशत) ऑनलाइन माध्यम से सदस्यों द्वारा भेजे गए, जिन्हें पब्लिक पोर्टल पर भी उपलब्ध कराया गया। उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही के दौरान कुल 408 याचिकाएं प्राप्त हुईं, जबकि तृतीय सत्र में नियम–311 के अंतर्गत कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। शीतकालीन सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों को भी पारित किया गया।

आयकर विभाग की लुलु मॉल पर बड़ी कार्रवाई, 27 करोड़ टैक्स न देने पर कंपनी का बैंक खाता फ्रीज

लखनऊ ब्यूरो, लखनऊ। आयकर विभाग ने लुलु मॉल के दो खातों को सीज कर दिया है। मॉल पर 27 करोड़ रुपये का बकाया है। आयकर विभाग लखनऊ के उपनिदेशक सर्किल एक ने ये कार्रवाई की है। लुलु मॉल पर लंबे समय से बकाया है। आयकर विभाग ने मॉल प्रशासन को इसके लिए कई नोटिस भेजे। सूत्रों के मुताबिक नोटिस का कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला।

बकाया 27 करोड़ रुपये टैक्स भी नहीं जमा किया गया। जिसके बाद विभाग ने मॉल के दो खातों को सीज कर दिया है। फिलहाल मॉल प्रशासन इन खातों को ऑपरेट नहीं कर सकेंगे। कोई भी रकम निकालने की अनुमति नहीं होगी। खातों में रकम जमा हो सकती है। नियमानुसार जो भी टैक्स बनेगा उसे जमा करना होगा, तभी खाते रिलीज किए जाएंगे। आकयर विभाग अब लेनदेन पर निगरानी भी बढ़ा दी है।

नियम ताक पर... करोड़ों का खेल, एसआईटी जांच ने खोली पोल, 42 मदरसा प्रबंधक फंसे

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में मदरसों की मंजूरी और सरकारी धन के दुरुपयोग से जुड़ा घोटाला सामने आया है। विशेष जांच दल (एसआईटी) की जांच में मिर्जापुर में 89 मदरसों की मंजूरी में गंभीर गड़बड़ियां मिली हैं। इन्हें पहले फर्जी ढंग से मान्यता दी गई। बाद में मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत यहां तैनात शिक्षकों को बिना सत्यापन के अवैध रूप से 10 करोड़ रुपये से ज्यादा का भुगतान किया गया। एसआईटी की जांच रिपोर्ट में 42 मदरसा प्रशासकों के साथ–साथ मिर्जापुर में तैनात रहे तीन जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी और कर्मचारी दोषी पाए गए हैं। रिपोर्ट में मिर्जापुर के दो तत्कालीन जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, दो क्लर्क, एक कंप्यूटर ऑपरेटर और 42 मदरसा प्रबंधकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा एक अन्य तत्कालीन जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी पर 2017 में बिना सत्यापन के डिजिटल हस्ताक्षरों के माध्यम से मदरसों को लॉक करने और लगभग 1 करोड़ 94 लाख रुपये का भुगतान करने का आरोप है। उनके खिलाफ विभागीय जांच की संस्तुति की गई है। वर्ष 2020 में निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण की सिफारिश पर मामले की जांच एसआईटी को सौंपी गई थी। मिलीभगत करके सरकारी आदेशों और उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम–2004 का उल्लंघन किया। अधिनियम के अनुसार कोई भी गैर मुस्लिम द्वारा स्थापित या संचालित मदरसे विधि मान्य नहीं होंगे, लेकिन एक मदरसे के संचालक को मुस्लिम न होने पर भी योजना

अल्पसंख्यक कल्याण की प्रमुख सचिव संयुक्ता समद्दार ने बताया कि एसआईटी की रिपोर्ट मिली है। इसका परीक्षण कराया जा रहा है। मिर्जापुर में एसआईटी की जांच में खुलासा... जांच में यह भी पता चला कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों ने मदरसों के प्रशासकों के साथ का लाभ दिया गया। मानकों को ताक पर रखकर मदरसों को अस्थायी मंजूरी दी गई। इन मदरसों के रिकॉर्ड की उचित जांच किए बिना ही शिक्षकों के वेतन के लिए बजट मांगा गया और कुछ ऐसे मदरसों को भी भुगतान कर दिया गया, जिनके लिए बजट स्वीकृत नहीं किया गया था।

केंद्र सरकार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, लव अग्रवाल बने डीजीएफटी प्रमुख, एफसीआई की कमान रवींद्र को

दिल्ली ब्यूरो

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल करते हुए कई अहम विभागों में शीर्ष अधिकारियों की नई नियुक्तियां की हैं। इस फेरबदल में वरिष्ठ नौकरशाह लव अग्रवाल को विदेश व्यापार महानिदेशालय का प्रमुख बनाया गया है, जबकि भारतीय खाद्य निगम की जिम्मेदारी रवींद्र कुमार अग्रवाल को सौंपी गई है। इस कदम को नीति निर्माण और प्रशासनिक कामकाज को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार, इन सभी नियुक्तियों को मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति की मंजूरी मिली है। यह फेरबदल केवल दो पदों तक सीमित नहीं है, बल्कि कुल 25 सिविल सेवकों को अलग–अलग केंद्रीय विभागों में नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। डीजीएफटी की कमान लव अग्रवाल के हाथ 1996 बैच के आईएएस अधिकारी लव अग्रवाल, जो आंध्र प्रदेश कैडर के हैं, को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत विदेश व्यापार महानिदेशालय का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इससे पहले वह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत थे। डीजीएफटी देश के आयात–निर्यात और विदेशी व्यापार नीतियों से जुड़ा अहम विभाग है। एफसीआई में नेतृत्व बदलाव सहकारिता मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव रहे रवींद्र अग्रवाल को भारतीय खाद्य निगम का चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। वह अशुतोष अग्निहोत्री की जगह लेंगे। अशुतोष अग्निहोत्री को अब पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव बनाया गया है। ऊर्जा और वाणिज्य विभाग में नई जिम्मेदारियां बिजली मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव रहे श्रीकांत नागुलापल्ली को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय का

महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वहीं, 1992 बैच के भारतीय रक्षा लेखा सेवा अधिकारी सुचिंद्र मिश्रा को वाणिज्य विभाग में विशेष सचिव बनाया गया है। कौशल मंत्रालय में फेरबदल राष्ट्रपति सचिवालय में अतिरिक्त सचिव रहे राकेश गुप्ता को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में अतिरिक्त सचिव बनाया गया है। उर्वरक विभाग की अतिरिक्त सचिव अनीता सी मेषराम को राष्ट्रपति सचिवालय भेजा गया है। इसके अलावा, पंजाब कैडर के आईएएस अधिकारी दिलीप कुमार को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय में महानिदेशक (प्रशिक्षण) नियुक्त किया गया है। उन्नयन और नई नियुक्तियां सरकार ने दो अधिकारियों को विशेष सचिव स्तर तक इन–सिटू उन्नयन भी दिया है। कपड़ा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार रहे असित गोपाल अब विशेष सचिव होंगे। इसके साथ ही 13 अधिकारियों को अतिरिक्त सचिव स्तर पर पदोन्नति दी गई है। बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में संयुक्त सचिव रहे मुकेश मंगल तथा खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की संयुक्त सचिव अनीता कर्ण को अतिरिक्त सचिव बनाया गया है।

अंडमान की धरती पर गृह मंत्री का दौरा, दो जनवरी से शुरू करेंगे अहम बैठकों का सिलसिला

दिल्ली ब्यूरो

नई दिल्ली। केंद्र सरकार की नीतियों और आंतरिक सुरक्षा से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दो जनवरी को अंडमान और निकोबार द्वीप के दौरे पर पहुंचेंगे। इस दौरे को प्रशासनिक और रणनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार, गृह मंत्री दो जनवरी को अंडमान पहुंचेंगे और यहां कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। उनका यह दौरा संसदीय सलाहकार समिति की बैठक और कानूनी सुधारों से जुड़े कार्यक्रमों पर केंद्रित रहेगा। दो जनवरी को आगमन गृह मंत्री अमित शाह दो जनवरी को श्री विजयापुरम पहुंचेंगे। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत उपराज्यपाल डीके

जोशी करेंगे। उनके आगमन को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। तीन जनवरी को संसदीय बैठक तीन जनवरी को गृह मंत्री गृह मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। यह बैठक वांडूर में होगी, जहां गृह मंत्रालय से जुड़े अहम विषयों पर चर्चा की जाएगी। कानूनी सुधारों पर कार्यक्रम इसी दिन गृह मंत्री डॉ. बी आर आंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान के सभागार में भारतीय न्याय संहिता से जुड़े एक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में कानून व्यवस्था और न्याय प्रणाली पर विचार रखे जाएंगे। चार जनवरी को वापसी गृह मंत्री चार जनवरी को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से रवाना होंगे। इससे पहले वे प्रशासनिक अधिकारियों से अनौपचारिक बातचीत भी कर सकते हैं। सीडीएस का भी दौरा इसी दौरान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान भी दो जनवरी को अंडमान पहुंचेंगे। तीन जनवरी को वे कार निकोबार और अंडमान–निकोबार कमान का दौरा कर वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों से बातचीत करेंगे।

जन सांस्कृतिक समागम में बोलीं राष्ट्रपति मुर्मू-आदिवासी समुदाय के विकास के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण

एजेंसी

गुमला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आदिवासी समुदाय के विकास के लिए शिक्षा के महत्व पर बल देते हुए मंगलवार को शिक्षित व्यक्तियों से आग्रह किया कि वे लोगों को विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने में मदद करें। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार आदिवासी समुदाय के समावेशी विकास के लिए काम कर रही है, ताकि विकास समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। मुर्मू ने झारखंड के

गुमला जिले में अंतरराज्यीय जनसांस्कृतिक समागम समारोह–कार्तिक यात्रा (अंतरराज्यीय लोक सांस्कृतिक सभा) को संबोधित करते हुए यह बात कही। इस समागम में मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ और ओडिशा राज्य के आदिवासी समुदायों के लोगों ने भाग लिया। मुर्मू ने कहा, "शिक्षा विकास की कुंजी है। शिक्षा व्यक्तित्व को निखारती है, विकास के अवसर पैदा करती है और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय का माध्यम बनती है।" उन्होंने कहा कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद, कई लोग शहरों में बसना पसंद करते हैं और अपने गांवों में वापस नहीं लौटते हैं। राष्ट्रपति ने कहा, "हमें अपने गांव जाना चाहिए और लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं तथा उनके लाभों के बारे में उन्हें जागरूक करना चाहिए। सरकार अपना काम करेगी, लेकिन शिक्षा प्राप्त करने के बाद हमें भी अपना योगदान देना चाहिए।" इस समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय भी मौजूद थे। उन्होंने कहा, "यह सरकार आदिवासी समुदाय के समावेशी विकास में विश्वास रखती है और समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने के लिए काम कर रही है। सरकार ने बिरसा मुंडा के नाम से कई योजनाएं शुरू की हैं।

संपादकीय

उन्नाव पीड़िता को थोड़ी राहत

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उन्नाव बलात्कार मामले में दोषी पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने दिल्ली हाईकोर्ट के 23 दिसंबर के उस आदेश के लागू होने पर स्टे ऑर्डर जारी किया, जिसमें सेंगर की आजीवन कारावास की सजा निलंबित कर उन्हें अपील लंबित रहने तक जमानत दी गई थी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, श्विशेष तथ्यों को देखते हुए, जहां दोषी एक अलग अपराध में भी सजा काट रहा है, हम दिल्ली हाईकोर्ट के 23 दिसंबर 2025 के आदेश को लागू करने पर रोक लगाते हैं। इस प्रकार, आरोपी को उक्त आदेश के तहत रिहा नहीं किया जाएगा।इस फैसले से एक बड़ी राहत पीड़िता को मिली है, क्योंकि अब यह तो तय हो गया है कि बलात्कार के दोष में कुलदीप सिंह सेंगर जेल में ही रहेगा, अब भी पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के एक अलग मामले में वह 10 वर्ष की सजा काट ही रहा है। इसमें उसे जमानत नहीं मिली है और अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद है। लेकिन अगर इस मामले में भी जमानत मिल जाती तब तो पीड़िता के लिए खतरा और ज्यादा बढ़ जाता। सेंगर ने केवल एक नाबालिग मासूम का बलात्कार ही नहीं किया, बल्कि अपने राजनैतिक दबदबे का इस्तेमाल उसकी इंसाफ की लड़ाई को रोकने में भी किया। इसलिए जब हाईकोर्ट ने सेंगर को जमानत दी थी, तो उसने इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाई थी। उसका साथ देने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता योगिता भयाना सामने आईं। हालांकि यह देखकर बेहद अफसोस हुआ कि इंसाफ के लिए लड़ रहे इन लोगों को पुलिस प्रशासन ने कुचलने की तमाम कोशिशें कीं। इंडिया गेट से लेकर संसद और हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने तक जहां भी कुलदीप सेंगर को जमानत मिलने का विरोध करने के लिए पीड़िता के साथ लोग इकत्र्रे हुए उन्हें वहां से बलपूर्वक भगाने की कोशिशें हुईं। समझ नहीं आता कि आखिर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों से किस बात का खतरा सरकार को दिखाई देता है। देश में कितने ही मामले ऐसे सामने आते हैं जहां गुंडे कभी रेस्तरां, कभी पार्क में बैठे लोगों को परेशान करने, प्रताड़ित करने पहुंच जाते हैं। तब पुलिस पता नहीं कहां गायब हो जाती है। अभी देहरादून में अंजेल चकमा नाम के युवा को नस्लभेदी नफरत के कारण मार दिया गया। उसे चायनीज और मोमो जैसे शब्द बोलकर अपमानित किया गया। वह कहता रहा कि वह भारतीय है, फिर भी उसकी जान ले ली गई। हालांकि वह भारतीय न भी होता, सच में चीन या किसी और देश का नागरिक होता, तब भी नस्लीय नफरत और हिंसा के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऐसे उत्पीड़न जब हो रहे होते हैं, तब पुलिस वहां नहीं पहुंचती। भाजपा के शासन में पुलिस का भी राजनीतिकरण करने के जो आरोप लगते हैं, वो ऐसी घटनाओं के बाद सही लगते हैं।कुलदीप सेंगर मामले में शर्मनाक बात यह है कि भाजपा के कई नेता उसके समर्थन में खुलकर आ गए हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह ने सेंगर को जमानत देने का स्वागत किया था, योगी सरकार में मंत्री ओ पी राजभर ने भी पीड़िता का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि उसका घर उन्नाव में है तो दिल्ली में प्रदर्शन की क्या जरूरत। इसके बाद भाजपा पर कुलदीप सेंगर को राजनीतिक संरक्षण देने का जो आरोप लगा है, वह भी प्रमाणित होता दिखाई देता है। सब जानते हैं कि बलात्कार का गंभीर आरोप लगने के बावजूद लंबे समय तक कुलदीप सेंगर को गिरफ्तार नहीं किया गया। भाजपा ने लगातार इस मामले में लीपापोती की। अभी जमानत मिलने के बाद जब पीड़िता, उसकी मां और योगिता भयाना आदि विरोध के लिए सड़कों पर थे तो कुछ लोग सेंगर के समर्थन में पोस्टर लेकर उनसे भिड़ने आ गए। इनमें एक महिला भी थी, जो बार–बार कह रही थी कि इस मामले का राजनीतकरण किया जा रहा है। अफसोस की बात ये है कि मुख्यधारा का मीडिया ऐसे लोगों को बराबरी से कवरेज दे रहा था, मानो यही निष्पक्ष पत्रकारिता की कसौटी है। हालांकि एक पत्रकार ने सेंगर के समर्थन में आवाज उठा रही महिला से पूछ लिया कि आपकी बेटी के साथ ऐसा होता क्या तब भी आप बलात्कारी के लिए ऐसे ही सामने आती, तो वह महिला बिना जवाब दिए चली गई। इससे साफ समझ आ रहा है कि कैसे सेंगर के पक्ष में माहौल बनाकर पीड़िता के हौसले को कुचला जा रहा था। जहां तक मामले के राजनीतिकरण की बात है, तो पीड़िता किसी राजनीतिक दल से नहीं है, न ही उसे अपने लिए इंसाफ किसी राजनैतिक फायदे के लिए चाहिए। यह विशुद्ध नारी अस्मिता और मानवीय गरिमा की रक्षा की लड़ाई है, जिसमें बार–बार पीड़िता को कटघरे में खड़ा कर अन्याय को बढ़ाया जा रहा है।

राशिफल

मेष :– व्यावसाय में लाभ की संभावना है ऐसा गणेशजी कहते हैं। नौकरी व व्यापार में सहकर्मियों से सहयोग नहीं मिलेगा। लंबी यात्रा का आयोजन हो सकता है। अस्वस्थ रहेंगे।

वृषभ :– मन को स्थिर रखने की सलाह गणेशजी देते हैं, क्योंकि अर्निणय की मनोदशा से अवसर गवां सकते हैं। प्रवास का आयोजन टाल दें। नए कार्य प्रारंभ न करें।

मिथुन :– लक्ष्मीजी की कृपा से दिन लाभदायी होगा। उत्तम भोजन, सुंदर वस्त्र व अपनों के साथ से दिन आनंददायी होगा। धन अधिक व्यय न करें।

कर्क :– गणेशजी कहते हैं कि आप में उत्साह व स्फूर्ति की कमी होगी। परिजनों के साथ विवाद न करें। अस्वस्थ महसूस करेंगे। नौकरी में चिंता रहेगी। धन व कीर्ति की हानि न हो ध्यान रखें।

सिंह :– आज का दिन लाभदायी है। मित्रों से लाभ और पर्यटन की संभावना है। हाथ आया अवसर जा सकता है, इसलिए निर्णय टाल दें। व्यापार एवं आर्थिक लाभ के योग हैं।

कन्या :– आज दिन शुभ है। नए कार्य संपन्न होंगे। व्यापारी व नौकरीपेशा लोगों के लिए समय अच्छा है। व्यापार में लाभ व नौकरी में पदोन्नति के योग हैं। पिता से लाभ होगा।

तुला :– आज का दिन शुभ और फलदायी होगा। महत्त्वपूर्ण निर्णय न लेने की सलाह है। यात्रा के योग हैं। लेखनकार्य के लिए अच्छा दिन है। महिला के साथ विवाद में न उतरें।

वृश्चिक :– आज शांति व सावधानीपूर्वक रूप से रहने की गणेशजी की सलाह है। नए कार्यों में असफलता के योग हैं। क्रोध पर संयम रखें। सरकार विरोधी प्रवृत्तियों से दूर रहें।

धनु :– आज का दिन आनंदपूर्वक बीतेगा। सहवास का आनंद मिलेगा। प्रवास, पर्यटन होगा। लेखनकार्य के दिन अनुकूल है। साझेदारी से लाभ होगा।

मकर :– व्यापार में विकास के लिए आज का दिन लाभकारी रहेगा। धन के लेनदेन में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। घर में सुख–शांति का वातावरण बना रहेगा।

कुंभ :– आप की वाणी व विचारों में शीघ्र परिवर्तन होगा। बौद्धिक चर्चा में शामिल होंगे। आकस्मिक खर्च की आशंका है। पाचन न होने जैसी बीमारियों से परेशान होंगे।

मीन :– कोई भी महत्त्वपूर्ण निर्णय न लें। संबंधियों से मनमुटाव हो सकता है। वाणी पर संयम रखें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मानहानि एवं धनहानि से बचें।

पूर्व और पश्चिम के बीच एक सेतु थे –नोबेल पुरस्कार विजेता रुडयार्ड किपलिंग

–सुनील कुमार महला

हमारे देश में शायद ही कोई बच्चा हो,जिसे श्जंगल बुकश के बारे में पता नहीं हो।सच तो यह है कि बच्चों की चहेती 'जंगल बुक' सबसे प्रिय और कालजयी कहानियों में से एक रही है। आपको याद होगा कि टेलीविजन पर श्जंगल जंगल बात चली है...श लोकप्रिय गीत श्द जंगल बुकश की दुनिया का परिचय देता है। वास्तव में, यह जंगल में श्मोगलीश(चरित्र) के आने की खबर है, जिसे सुनकर सभी जानवरों में उत्सुकता फैल जाती है। सरल धुन और कल्पनाशील शब्दों के कारण यह गीत बहुत समय पहले बच्चों में बेहद लोकप्रिय हुआ और आज भी बचपन की याद दिलाता है। पाठकों को बताता चलूं कि इसे विश्वप्रसिद्ध लेखक रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा था,जिसकी कहानी जंगल में पले–बढ़े बालक मोगली के इर्द–गिर्द घूमती है, जिसे भेड़ियों का झुंड पालता है। मोगली के मित्र बालू भालू उसे जीवन के सरल नियम सिखाते हैं, बघीरा उसे सुरक्षा और समझदारी का पाठ पढ़ाता है, जबकि खतरनाक शेर खान कहानी में रोमांच और संघर्ष का तत्व जोड़ता है। जंगल बुक केवल मनोरंजन नहीं करती, बल्कि बच्चों को मित्रता, साहस, अनुशासन, प्रकृति–प्रेम और नैतिक मूल्यों की सीख भी देती है। इसकी सरल भाषा, जीवंत पात्र और रोमांचक घटनाएं बच्चों की कल्पनाशक्ति को उड़ान देती हैं। किताब के साथ–साथ इसके कार्टून और फिल्म रूपांतरणों ने भी इसे पीढ़ियों तक लोकप्रिय बनाए रखा है। बच्चों की सर्वाधिक चहेती और आम जन में लोकप्रिय उनकी कृति–श्जंगल बुकश, नोबेल पुरस्कार तथा भारत से लगाव आज के इस आधुनिक दौर में भी जबकि हम सभी एआइ और सोशल नेटवर्किंग साइट्स के युग में जी रहे हैं, तब भी 'जंगल बुकश लगातार बच्चों की चहेती/पसंदीदा कहानी बनी हुई है। रुडयार्ड किपलिंग ब्रिटिश लेखक, कवि और पत्रकार थे,जो साहित्य(लिटरेचर)के अत्यंत प्रभावशाली रचनाकारों(कविता, कहानी, उपन्यास) में गिने जाते हैं। यहां तक कि साहित्य में विशिष्ट योगदान के लिए उन्हें प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।उनका पूरा नाम जोसेफ रुडयार्ड किपलिंग था तथा उनका जन्म 30 दिसंबर 1865 को बॉम्बे (वर्तमान मुंबई), ब्रिटिश भारत में हुआ था तथा मृत्यु 18 जनवरी 1936 में हुई। रोचक तथ्य यह है कि उनका का नाम रुडयार्ड लेक (इंग्लैंड) से प्रेरित होकर रखा गया था तथा उनकी राष्ट्रीयता ब्रिटिश थी, लेकिन वे हर भारतीय बच्चों के दिलो–दिमाग में राज करते हैं।भले ही उनकी राष्ट्रीयता ब्रिटिश थी, लेकिन चूंकि उनका जन्म भारत में हुआ और उनका बचपन भी यहीं बीता, इसलिए भारत उनकी रचनात्मक चेतना में गहराई से रचा–बसा रहा।किपलिंग का जन्म भले ही बॉम्बे (मुंबई) में हुआ, लेकिन छह वर्ष की उम्र में ही उन्हें इंग्लैंड भेज दिया गया, जहाँ उन्होंने एक कठोर और भावनात्मक रूप से पीड़ादायक बचपन झेला। बाद में उन्होंने लिखा कि यह अनुभव उनके जीवन के सबसे काले अध्यायों में से एक था। दूसरे शब्दों में कहें तो ब्रिटिश नागरिकता के बाद हालांकि,उनकी भारत लौटने की इच्छा थी, पर वे कभी भारत नहीं लौट सके। वास्तव में, वे जीवनभर भारत लौटना चाहते थे, लेकिन परिस्थितियों ने अनुमति नहीं दी। कहा जाता है कि उन्होंने एक बार लिखा–श्भारत मुझे छोड़ गया, पर मैं भारत को कभी नहीं छोड़ सका।श तात्पर्य यह है कि भारत उनके दिलो–दिमाग में बसा हुआ रहा। सच तो यह है कि भारत की संस्कृति, भूगोल और सामाजिक जीवन उनके साहित्य में बार–बार झलकता है।वर्ष 1907 में उन्हें प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। वे साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले अंग्रेज़ी लेखक और उस समय के सबसे कम उम्र के विजेता थे। यहां उल्लेखनीय है कि 1907 में नोबेल पुरस्कार मिलने के बावजूद किपलिंग ने नोबेल व्याख्यान (नोबल लेक्चर) नहीं दिया तथा यह साहित्य के इतिहास में दुर्लभ उदाहरणों में से एक है। हाल फिलहाल,यदि हम यहां पर उनकी कुछ प्रमुख कृतियों की बात करें तो उनमें क्रमशः द जंगल बुक,जो उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना थी, श्किमश उपन्यास, श्जस्ट हो स्टोरीजश(बाल साहित्य) तथा श्इफश उनकी विश्व की सर्वाधिक चर्चित कविताओं में से एक मानी जाती है।सच तो यह है कि उनकी कविता श्इफश को आज भी प्रेरणादायक जीवन–मंत्र की तरह पढ़ा जाता है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उनकी विश्वप्रसिद्ध कविता श्इफश किसी दर्शन ग्रंथ के लिए नहीं, बल्कि अपने बेटे जॉन के लिए लिखी गई निजी सीख थी–जिसमें,एक आदर्श पुरुष और जिम्मेदार नागरिक बनने का संदेश निहित था।चूंकि, वे भारत में जन्मे थे, इसलिए भारत के लोकजीवन से उनका गहरा जुड़ाव था।सच तो यह है कि किपलिंग को रेलवे स्टेशनों, सैनिक छावनियों, डाक–व्यवस्था और अखबारों का विशेष आकर्षण था और वे घंटों–घंटों तक आम लोगों से बातचीत कर कहानियों की सामग्री जुटाते थे।किपलिंग बाल साहित्य से पहले 'गंभीर लेखक' माने जाते थे तथा आज वे 'जंगल बुक' के कारण बाल साहित्यकार कहे जाते हैं, लेकिन अपने समय में वे राजनीतिक और साम्राज्यवादी विषयों पर लिखने वाले गंभीर लेखक माने जाते थे। जानकारी मिलती है कि प्रथम विश्व युद्ध में उनके इकलौते बेटे जॉन किपलिंग की मृत्यु हो गई थी और इस घटना के बाद किपलिंग का लेखन अत्यंत उदास और आत्ममंथन से भरा हो गया था।हालाँकि, उन्हें अपने समय का एक महान और बड़ा कवि कहा गया, लेकिन किपलिंग खुद को कहानीकार और पत्रकार मानते थे, कवि नहीं।किपलिंग ब्रिटिश साम्राज्यवाद(किसी शक्तिशाली देश का दूसरे देश पर अपने फायदे के लिए नियंत्रण करना) के समर्थक थे, इसी कारण आधुनिक समय में उन्हें विवादास्पद लेखक भी माना जाता है, और इसके कारण उनकी आलोचना भी हुई,लेकिन उनकी साहित्यिक प्रतिभा पर कोई विवाद नहीं है। पाठकों को बताता चलूं कि किपलिंग को मृत्यु के बाद वेस्टमिंस्टर ऐबे के 'पोएट्स कॉर्नर' में दफनाया गया था, तथा तह सम्मान बहुत कम लेखकों को मिलता है।हाल फिलहाल, यहां पाठकों को बताता चलूं कि श्द मैन हू वुड बी किंगश रुडयार्ड किपलिंग की प्रसिद्ध और विचारोत्तेजक कहानी है, जो सत्ता, महत्वाकांक्षा और मानवीय अहंकार पर तीखा व्यंग्य करती है।यह कहानी दो ब्रिटिश साहसी व्यक्तियों–डैनियल ड्रावोट और पीची कार्नाहन के इर्द–गिर्द घूमती है, जो भारत से आगे काफिरिस्तान पहुँचकर स्वयं को राजा घोषित करने का सपना देखते हैं। वास्तव में यह कहानी केवल रोमांच नहीं, बल्कि एक गहरी सीख भी देती है कि शक्ति बिना विवेक के विनाशकारी होती है, और मनुष्य जब खुद को ईश्वर समझने लगता है, तब उसका अंत निश्चित होता है। साहित्यिक विशेषताएं तथा किपलिंग का साम्राज्य–बोध बहरहाल,उनकी साहित्यिक विशेषताओं की यदि हम यहां पर बात करें तो उनकी रचनाओं में औपनिवेशिक भारत, प्रकृति, साहस, अनुशासन और नैतिक मूल्यों का गहरा चित्रण मिलता है। वे बाल साहित्य और कविता दोनों में समान रूप से लोकप्रिय रहे तथा उनकी भाषा सरल, कथानक सशक्त और पात्र अत्यंत जीवंत होते थे। अंत में यही कहूंगा कि रुडयार्ड किपलिंग को अक्सर केवल 'जंगल बुक' के लेखक के रूप में याद किया जाता है, जबकि उनका साहित्यिक व्यक्तित्व इससे कहीं अधिक व्यापक और गहन है।सच तो यह है कि वे ऐसे लेखक थे, जिन्होंने अपने निजी जीवन के अनुभवों–विशेषकर विस्थापन और अकेलेपन की पीड़ा को अपने लेखन की सहायता से रचनात्मक रूप दिया। कहना ग़लत नहीं होगा कि भारत में जन्म, फिर कम उम्र में इंग्लैंड भेजे जाने का अनुभव उनके भीतर स्थायी मानसिक संघर्ष छोड़ गया, जो उनकी रचनाओं में बार–बार उभरता है। इसी कारण उनके पात्र केवल कहानी नहीं कहते, बल्कि मनुष्य की आंतरिक लड़ाइयों, असुरक्षाओं और नैतिक द्वंद्वों को भी कहीं न कहीं उजागर करते हैं। किपलिंग का साम्राज्य–बोध भी सरल नहीं था। दरअसल, वे ब्रिटिश साम्राज्य के युग के लेखक थे, पर उनकी रचनाओं में सत्ता के साथ–साथ कर्तव्य, अनुशासन और नैतिक जिम्मेदारी पर भी गहन चिंतन मिलता है। किपलिंग की कविता 'इफ' इंसान को सिखाती है कि मुश्किल हालात में भी धैर्य बनाए रखना चाहिए, तथा साहस नहीं छोड़ना चाहिए और अपने व्यवहार में संतुलन बनाए रखना चाहिए।उनकी लोकप्रिय कृति 'जंगल बुक' में बताए गए नियम केवल जंगल के नहीं हैं, बल्कि वे कहीं न कहीं मानव समाज के नियमों जैसे हैं, जहाँ अनुशासन, मर्यादा और जिम्मेदारी ज़रूरी होती है और यह बात जिन्होंने श्जंगल बुकश को टेलीविजन पर देखा है, उससे साफतौर पर पता चलती है। वास्तव में सच तो यह है कि किपलिंग अंधी ताकत या ज़ोर–जबरदस्ती का कहीं भी किसी भी स्टेज पर समर्थन करते नजर नहीं आते हैं, बल्कि वे यह बताते नजर आते हैं कि असली शक्ति नैतिकता, आत्मसंयम और सही आचरण में होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रुडयार्ड किपलिंग पूर्व और पश्चिम के बीच एक सेतु थे। गौरतलब है कि भारतीय संस्कृति, प्रकृति, लोककथाओं और जीवन–दृष्टि को उन्होंने पश्चिमी पाठकों तक पहुँचाया, वहीं पश्चिमी अनुशासन और सोच को भारतीय परिवेश में रखकर देखा। यही द्विसांस्कृतिक दृष्टि उनकी रचनाओं को आमजन में सार्वकालिक और लोकप्रिय बनाती है। इसलिए किपलिंग को समझना केवल उनके लोकप्रिय चेहरे को जानना नहीं, बल्कि उस गहराई को महसूस करना है जहाँ साहित्य, संस्कृति और मनुष्य का अंतर्मन एक–दूसरे से संवाद करते हैं।

उपलब्धियों के शोर में दबे सच : 2025 का आत्ममंथन

बीता साल, बचे सवाल : 2025 का भारत

– डॉ सत्यवान सौरभ

इतिहास केवल तारीख़ों और घटनाओं का संग्रह नहीं होता, वह समाज की सामूहिक चेतना का आईना भी होता है। बीते कुछ वर्ष, और विशेष रूप से वर्ष 2025, भारत के लिए ऐसा ही एक आईना बनकर सामने आएकृ जिसमें हमने अपनी उपलब्धियाँ भी देखीं और अपनी असहज सच्चाइयाँ भी। यह वर्ष उम्मीद और हताशा, प्रगति और पिछड़ेपन, गर्व और ग्लानिकृइन सभी भावों का एक साथ साक्षी बना।

2025 में भारत ने कई मोर्चों पर दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। डिजिटल भुगतान प्रणाली ने आम नागरिक के जीवन को अपेक्षाकृत सरल बनाया। यूपीआई जैसी तकनीकों ने यह दिखाया कि यदि नीयत हो तो तकनीक जनसाधारण तक पहुँच सकती है। स्टार्टअप संस्कृति ने युवाओं में उद्यमिता का विश्वास जगाया, अंतरिक्ष अनुसंधान में भारत ने सीमित संसाधनों में असाधारण क्षमताओं का परिचय दिया, और बुनियादी ढाँचेकृसड़कों, रेल, हवाई अड्डोंकृके विस्तार ने 'तेज़ी से बढ़ते भारत' की छवि को मज़बूत किया। इन उपलब्धियों से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन यहीं आत्ममंथन की ज़रूरत भी पैदा होती है, क्योंकि सवाल केवल विकास का नहीं, बल्कि उसके सामाजिक प्रभाव का है।

विकास के चमकदार आँकड़ों के समानांतर 2025 में बेरोज़गारी और महंगाई की सच्चाई भी उतनी ही तीखी रही। पढ़े–लिखे युवाओं के हाथों में डिग्रियाँ थीं, लेकिन रोज़गार नहीं। भर्ती परीक्षाओं की अनिश्चितता, परिणामों में देरी और निजी क्षेत्र की अस्थिरता ने एक पूरी पीढ़ी को मानसिक दबाव में डाल दिया। महंगाई ने आम आदमी की रसोई से संतुलन छीन लिया। दाल–सब्ज़ी, गैस, शिक्षा और स्वास्थ्यकृसब कुछ महँगा होता गया, पर आय उसी अनुपात में नहीं बढ़ी। यह आर्थिक असंतुलन धीरे–धीरे सामाजिक असंतोष में बदलता चला गया।

2025 में किसान और मज़दूर की स्थिति भी किसी से छिपी नहीं रही। मौसम की मार, फसल के उचित दाम न मिलना, बढ़ता कर्ज़ और नीति–स्तर की अनदेखी ने किसान को लगातार असुरक्षा में रखा। कहीं संवाद टलता रहा, कहीं आंदोलनों को दबाने की कोशिश हुई। यह विडंबना है कि जो देश को भोजन देता है, वही सबसे अधिक अनिश्चित भविष्य से घिरा है। मज़दूरों की स्थिति भी इससे भिन्न नहीं रही। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों लोग सामाजिक सुरक्षा, स्थायी रोज़गार और सम्मानजनक जीवन से वंचित रहे। विकास की इमारत जिन हाथों से खड़ी होती है, वे हाथ अक्सर सबसे ज़्यादा थके और सबसे कम सुरक्षित होते हैं।

सार्वजनिक शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था की जर्जर हालत 2025 में और अधिक उजागर हुई। सरकारी स्कूलों और अस्पतालों की बदहाली अब किसी एक राज्य की समस्या नहीं, बल्कि राष्ट्रीय चुनौती बन चुकी है। शिक्षक संसाधनों की कमी और प्रशासनिक दबाव के बीच काम करते रहे, वहीं स्वास्थ्यकर्मी अत्यधिक कार्यभार, सीमित सुविधाओं और असुरक्षा के वातावरण में अपनी ज़िम्मेदारी निभाते रहे। निजीकरण ने विकल्प तो दिए, लेकिन समानता नहीं। शिक्षा और स्वास्थ्य धीरे–धीरे अधिकार की जगह बाज़ार की वस्तु बनते चले गए, और इसका सबसे बड़ा नुकसान उन लोगों को हुआ जो पहले से ही सामाजिक–आर्थिक रूप से कमजोर थे।

लोकतंत्र की दृष्टि से भी 2025 एक बेचैन करने वाला वर्ष रहा। असहमति को देशविरोध से जोड़ने की प्रवृत्ति ने सार्वजनिक विमर्श को संकुचित किया। लेखकों, पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं पर बढ़ता दबाव यह संकेत देने लगा कि सत्ता से सवाल पूछना जोखिम भरा होता जा रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर गिरफ्तारियाँ, अभिव्यक्ति की सीमाएँ तय करने की कोशिशें और संवैधानिक संस्थानों की स्वायत्तता पर उठते प्रश्न यह याद दिलाते रहे कि लोकतंत्र केवल चुनावी प्रक्रिया से जीवित नहीं रहता। वह जीवित रहता है स्वतंत्र प्रेस, निर्भीक नागरिकों और जवाबदेह संस्थानों से।

धर्म और पहचान की राजनीति ने 2025 में समाज को बार–बार विभाजित किया। धार्मिक उन्माद, भीड़तंत्र की मानसिकता और नैतिक पुलिसिंग ने संविधान में निहित समानता, बंधुत्व और धर्मनिरपेक्षता के मूल विचारों को चुनौती दी। धर्म, जो व्यक्ति का निजी आस्था–क्षेत्र होना चाहिए था, वह सत्ता और राजनीति का औज़ार बनता चला गया। इसका परिणाम यह हुआ कि समाज में अविश्वास बढ़ा, संवाद टूटा और मानवीय रिश्तों में दरारें गहराती चली गईं।

इन तमाम निराशाजनक स्थितियों के बीच 2025 ने उम्मीद की कुछ ठोस झलकें भी दीं। युवाओं ने सवाल पूछे, छात्रों ने अपनी आवाज़ बुलंद की, किसानों और कर्मचारियों ने संगठित होकर अपने अधिकारों की माँग की। नागरिक संगठनों और स्वतंत्र पत्रकारिता ने यह साबित किया कि भारतीय लोकतंत्र पूरी तरह मौन नहीं हुआ है। यह प्रतिरोध केवल सत्ता के विरुद्ध नहीं था, बल्कि उस सामाजिक उदासीनता के विरुद्ध भी था जो धीरे–धीरे हमें भीतर से खोखला कर देती है।

2025 ने यह स्पष्ट कर दिया कि विकास को केवल जीडीपी के आँकड़ों से नहीं मापा जा सकता। जब तक गाँव सुरक्षित नहीं होंगे, किसान आश्वस्त नहीं होगा, मज़दूर सम्मान के साथ नहीं जिएगा, शिक्षक और स्वास्थ्यकर्मी संरक्षित नहीं होंगे, और छात्र भविष्य को लेकर भयमुक्त नहीं होंगे, तब तक 'विकसित भारत' केवल एक आकर्षक नारा ही बना रहेगा। तकनीक तभी सार्थक है जब वह मानवीय संवेदनाओं से जुड़ी हो, और शासन तभी सफल माना जा सकता है जब उसका प्रभाव अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुँचे।

बीते वर्षों, और विशेषकर 2025 की सबसे बड़ी सीख यही है कि भारत को बचाने की ज़िम्मेदारी केवल सरकारों की नहीं, बल्कि जागरूक नागरिकों की भी है। लोकतंत्र में चुप्पी तटस्थता नहीं होती; वह अक्सर अन्याय की सबसे मज़बूत सहयोगी बन जाती है। जब हम अन्याय देखकर चुप रहते हैं, तब हम अनजाने में उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। 2025 ने हमें यह एहसास कराया कि अब चुप रहना विकल्प नहीं रहा। सवाल करना, असहमति जताना और संवाद बनाए रखना ही आज का सबसे बड़ा देशप्रेम है।

2025 केवल एक बीता हुआ वर्ष नहीं है, बल्कि एक चेतावनी और एक अवसर दोनों है। चेतावनी इस बात की कि यदि हमने असमानता, असहिष्णुता और दमन को सामान्य मान लिया, तो लोकतंत्र भीतर से खोखला हो जाएगा। और अवसर इस बात का कि हम विकास की दिशा, राजनीति की भाषा और नागरिक भूमिकाकृतीनों पर गंभीर पुनर्विचार कर सकते हैं। यदि 2025 से हमने सच में कुछ सीखा है, तो वही सीख आने वाले वर्षों को अधिक मानवीय, अधिक न्यायपूर्ण और अधिक लोकतांत्रिक बना सकती है।

पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल, पुडुचेरी विधानसभा चुनावों में कौन मारेगा बाजी?

–नीरज कुमार दुबे

साल 2025 भारतीय राजनीति में सत्ताधारी एनडीए के लिये विजय का वर्ष रहा। दिल्ली और बिहार में मिली निर्णायक जीत ने भारतीय जनता पार्टी के आत्मविश्वास को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया। दूसरी ओर विपक्ष के लिये यह साल निराशा, विघटन और हताशा का प्रतीक बन गया। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पराजित हुई और बिहार में कांग्रेस, राजद और वाम दलों का महागठबंधन लगभग साफ हो गया। लेकिन राजनीति में स्थायी कुछ नहीं होता। 2026 एक नये युद्ध का वर्ष है जहां सत्ता की जड़ें हिलाने के लिए विपक्ष फिर से प्रयास करेगा। हम आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। मार्च से मई 2026 के बीच होने वाले इन चुनावों के लिये सभी दल अभी से तलवारें निकाल चुके हैं। अभी से नेताओं के भाषणों में आग है, रणनीतियों में धार है और हर कदम सत्ता की लालसा से भरा हुआ है। सबसे पहले पश्चिम बंगाल की बात करें तो आपको बता दें कि राज्य में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस एक मजबूत किले की तरह खड़ी है, लेकिन इस किले की दीवारों पर अब लगातार भगवा हमले हो रहे हैं। 2016 में मात्र तीन सीटों पर सिमटी भाजपा 2021 में 77 सीटों तक पहुंच गयी। यह उछाल संयोग था या स्थायी चुनौती, इसका फैसला 2026 करेगा। ममता बनर्जी 213 सीटों और लगभग आधे वोट प्रतिशत के साथ सत्ता में हैं, लेकिन सत्ता का बोझ भारी होता है। महंगाई, बेरोजगारी और स्थानीय असंतोष अब उनके सामने खड़े बड़े सवाल हैं। भाजपा पूरी ताकत से मैदान में उतर चुकी है और बिहार की जीत के बाद उसका हौसला दोगुना है। वहीं कांग्रेस और वाम दल अपनी खोई हुई जमीन तलाश रहे हैं, लेकिन उनका संकट यह है कि जनता अब उन्हें गंभीर विकल्प मानने को तैयार नहीं है। विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मतदाता सूचियों में हो रहे बदलाव ने बंगाल की राजनीति में आग और घी का काम किया है। अल्पसंख्यक और शहरी क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तन चुनावी गणित को पूरी तरह पलट सकते हैं। वहीं तमिलनाडु की बात करें तो राज्य हमेशा से द्रविड राजनीति का गढ़ रहा है। द्रमुक और अन्नाद्रमुक के बीच सत्ता की रस्साकशी अब एक बार फिर चरम पर है। मुख्यमंत्री स्टालिन के नेतृत्व में द्रमुक मजबूत स्थिति में है, लेकिन सत्ता विरोधी लहर की आहट साफ सुनाई दे रही है। रोजगार, नीट, बिजली दरें और प्रशासनिक अपेक्षाएं सरकार के लिये अग्निपरीक्षा हैं। अन्नाद्रमुक और भाजपा का गठबंधन इस बार ज्यादा संगठित दिख रहा है। अन्नाद्रमुक महासचिव पलानीसामी का दावा है कि यह मोर्चा 200 से अधिक सीटें जीत सकता है। लेकिन इस गणित को सबसे ज्यादा बिगाड़ने वाला नाम है विजय। उनकी पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम पहली बार मैदान में है और युवा वर्ग में उसका असर नकारा नहीं जा सकता। हालांकि करूर की भगदड़ की घटना ने विजय की छवि को गहरी चोट पहुंचाई है। वहीं असम को देखें तो राज्य में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा भाजपा के सबसे आक्रामक चेहरों में गिने जाते हैं। 2021 में 75 सीटें जीतने के बावजूद सत्ता विरोधी भावना अब उभर रही है। सरमा का दावा है कि एनडीए 100 से अधिक सीटें जीतेगा, लेकिन राजनीति में दावे अक्सर जमीनी सच्चाई से टकराते हैं।

नया कोल्ड वार क्या है? किनके बीच चल रहा है? इसमें भारत किस भूमिका में है?

–कमलेश पांडेय

द्वितीय विश्व युद्ध की विजय के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच छिड़े शीत युद्ध और इसके वार–पलटवार जैसे युद्धगत प्रभावों से हमलोग वाकिफ हैं। इस दौरान यूएसए और यूएसएसआर की खेमेबाजी भी जगजाहिर रही, जिससे दुनिया के कमजोर देशों के कुछ कुछ हित भी सधे। हालांकि 1990 के दशक में सोवियत संघ के बिखराव के बाद यह खत्म हो गया। लेकिन अमेरिका की बढ़ती वैश्विक चौधराहट के बाद 2010 के दशक में अमेरिका–चीन के बीच फिर से एक श्नया शीत युद्धश शुरू हो गया, जो अब तलक जारी है। चूंकि यूएसएसआर के पतन में अमेरिकी भूमिका रही, इसलिए उसके अवशेष पर खड़े हुए रूस ने चीन को शह देकर अमेरिका से अपना पुराना हिसाब–किताब चुकता कर लिया। इस प्रकार दुनिया के थानेदार अमेरिका के सामने एक नई सामरिक–आर्थिक चुनौती खड़ी हो गई, लेकिन पारस्परिक होड़ का स्वरूप कुछ कुछ बदल गया। कुलमिलाकर चीन अब अमेरिका के लिए भस्मासुर साबित हो रहा है। इससे अमेरिका भारत की ओर मुड़ा, लेकिन भारतीय नेतृत्व की सतर्कता की वजह से 2025 आते आते अपने कुटिल इरादों में नाकामयाब हो गया। बताते चलें कि नया कोल्ड वार पुराने भू–सामरिक तनाव का ही एक परिवर्तित भू–राजनीतिक तनाव है, जो मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच चल रहा है। देखने में तो यह शीत युद्ध के जैसा ही है लेकिन यह प्रत्यक्ष सैन्य संघर्ष के बजाय आर्थिक, तकनीकी, व्यापारिक और वैचारिक प्रतिस्पर्धा पर केंद्रित है।

2025 : कृषि से इंडस्ट्री तक दौड़ा विकास का पहिया

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जनता के हित में लिए गए कई बड़े निर्णय
किसानों, युवाओं, महिलाओं, श्रमिकों, शिक्षकों और वंचित वर्गों तक पहुंचा सीधा लाभ
कृषि से लेकर उद्योग, शिक्षा, रोजगार, निवेश तक प्रदेश को मिली नई दिशा
वर्ष 2025 में लिए गए फैसले उत्तर प्रदेश के विकास की बने मजबूत नींव

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। वर्ष 2025 उत्तर प्रदेश के लिए नीति, निर्णय और परिणामों का वर्ष साबित हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार ने ऐसे कई ऐतिहासिक और दूरगामी फैसले लिए जिनका सीधा लाभ किसानों, युवाओं, महिलाओं, श्रमिकों, शिक्षकों और वंचित वर्गों तक पहुंचा। कृषि से लेकर उद्योग, शिक्षा से लेकर रोजगार, सामाजिक सुरक्षा से लेकर निवेश तक योगी सरकार के निर्णयों ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था और जनकल्याण को नई दिशा दी। दृढ़ इच्छाशक्ति और जनहित केंद्रित सोच के चलते वर्ष 2025 में लिए गए सीएम योगी आदित्यनाथ के ये फैसले उत्तर प्रदेश के विकास की मजबूत नींव बने। 1. शिक्षक : 9 लाख शिक्षकों को कैशलेस इलाज की सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के करीब 9 लाख शिक्षकों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने का ऐतिहासिक ऐलान किया। इस योजना में बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा के शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक और रसोइए भी शामिल किए गए। इससे शिक्षक और उनके परिवारों को बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा मिली। 2. कर्मचारी : आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम आउटसोर्स कार्मिकों के शोषण को समाप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम लिमिटेड का गठन किया गया। इसके माध्यम से अब पारदर्शी भर्ती, समय पर वेतन, ईपीएफ–ईएसआई, न्यूनतम 16 से 20 हजार रुपये मानदेय और रोजगार सुरक्षा सुनिश्चित हुई। 3. किसान : लघु व सीमांत किसानों को महज छह फीसदी पर मिलेगा लोन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अंतर्गत 21 दिसंबर को लघु व सीमांत किसानों के लिए बड़ी घोषणा की। मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत प्रदेश के लघु व सीमांत किसानों को यूपी सहकारी ग्राम विकास बैंक (एलडीबी) के माध्यम से महज 06 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण मिलेगा। अभी तक किसानों को इस बैंक से 11.50 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण मिलता था। ब्याज की शेष धनराशि राज्य सरकार वहन करेगी। गन्ना किसानों को बड़ी राहत, 30 रुपये प्रति क्विंटल इजाफा पेराई सत्र 2025–26 के लिए गन्ना के मूल्य में 30 रुपये प्रति क्विंटल की रिकॉर्ड वृद्धि की गई। इससे अगैती गन्ना 400, सामान्य 390 और अनुपयुक्त प्रजाति 355 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। इस फैसले से लाखों किसानों की आय में सीधा इजाफा हुआ। 4. युवा : उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक पुलिस भर्ती यूपी में 60,244 पुलिस सिपाहियों की ऐतिहासिक भर्ती के तहत नियुक्ति पत्र बांटे गए, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। यह भर्ती देश की सबसे बड़ी और पारदर्शी भर्तियों में से एक मानी गई। इसमें 12,000 से ज्यादा महिलाएं भी चयनित हुईं और इसे श्सुरक्षित उत्तर प्रदेशश व श्नए भारतश की दिशा में एक बड़ा कदम बताया गया। 5. विकास : 'प्रदेश के समग्र विकास के लिए 'विकसित यूपी अभियान' का शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के समग्र विकास के लिए श्समर्थ उत्तर प्रदेश–विकसित उत्तर प्रदेश /2047 महाअभियान का शुभारंभ किया है, जिसका उद्देश्य 2047 तक राज्य को विकसित बनाना है। इसके लिए श्समर्थ उत्तर प्रदेश पोर्टलश के माध्यम से जनता से सुझाव लिए जा रहे हैं, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और शहरी–ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों पर फोकस किया जा रहा है। ,त्र6. महिला सशक्तिकरण : महिलाओं को रजिस्ट्री शुल्क में 1% की अतिरिक्त छूट उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं को संपत्ति रजिस्ट्री शुल्क (Stamp Duty) में 1% की अतिरिक्त छूट दी है, जो पहले केवल 10 लाख रुपए तक की संपत्ति पर थी, उसे अब एक करोड़ रुपए तक की प्रॉपर्टी के लिए बढ़ाया गया है, जिससे उन्हें अधिकतम एक लाख रुपए तक की बचत हो सकती है और यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम कदम है, जिससे वे आर्थिक रूप से सशक्त बनें। 7. अग्निवीर : अग्निवीरों को यूपी पुलिस व पीएसी में 20% आरक्षण देश सेवा के बाद अग्निवीरों के पुनर्वास के लिए यूपी पुलिस और पीएसी भर्ती में 20 प्रतिशत आरक्षण का निर्णय लिया गया। इससे युवाओं का भविष्य सुरक्षित हुआ। 8. बेटियां : गरीब बेटियों के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में दोगुना अनुदान मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत विवाह अनुदान 51 हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपये किया गया। साथ ही आय सीमा बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दी गई,

जिससे हजारों गरीब परिवारों को राहत मिली। 9. महाकुंभ : महाकुंभ के अवसर पर कैबिनेट बैठक का ऐतिहासिक निर्णय महाकुंभ नगरी में कैबिनेट बैठक कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐतिहासिक निर्णय लिया। अयोध्या के बाद महाकुंभ नगर में कैबिनेट बैठक कर मुख्यमंत्री ने एक मिसाल पेश की। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने के बाद पूरी कैबिनेट ने एक साथ संगम स्नान भी किया। 10. बुजुर्ग : वृद्धावस्था पेंशन योजना को फैमिली आईडी से जोड़ा गया वृद्धावस्था पेंशन योजना को फैमिली आईडी से जोड़ने का निर्णय भी इसी वर्ष लिया गया। अमेठी, कासगंज, गोरखपुर, ललितपुर और बस्ती में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। 60 वर्ष की आयु पूरी करते ही पेंशन खाते में पहुंचने लगेगी। आवेदन की आवश्यकता नहीं होगी। फैमिली आईडी से स्वतः पहचान होगी और एसएमएस से सहमति ली जाएगी। ये योजनाएं भी रहीं महत्वपूर्ण महापुरुषों के नाम पर योजनाएं और संस्थान योगी सरकार ने बाबा साहब आंबेडकर के नाम पर छात्रावास, लोकमाता अहिल्याबाई के नाम पर महिला हॉस्टल, संत कबीरदास के नाम पर टेक्सटाइल पार्क, संत रविदास के नाम पर लेदर पार्क, चौधरी चरण सिंह के नाम पर सीड पार्क और अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर नगरीय पुस्तकालय बनाने का निर्णय लिया। इन फैसलों से सामाजिक समरसता और विकास को नई पहचान मिली। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी–चिवनिंग छात्रवृत्ति योजना योगी सरकार ने छात्रों को ब्रिटेन की आक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, इंपीरियल कालेज, लंदन स्कूल ऑफ इकोनामिक्स जैसी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में मास्टर्स की पढ़ाई करने के लिए 'भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी–चिवनिंग छात्रवृत्ति योजना' शुरू करने का निर्णय लिया। इस योजना के तहत प्रत्येक वर्ष प्रदेश के 5 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को यूनाइटेड किंगडम की किसी भी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में एक वर्षीय परास्नातक (मास्टर्स) डिग्री के लिए पूरी छात्रवृत्ति दी जाएगी। मेधावी छात्राओं के लिए रानी लक्ष्मी बाई स्कूटी योजना का ऐलान 2025 के बजट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को शुरू करने का ऐलान किया। इस योजना के तहत प्रदेश की मेधावी छात्राओं को निशुल्क स्कूटी दी जाएगी, ताकि वे अपनी शिक्षा को निर्बाध रूप से जारी रख सकें। यह योजना खासतौर पर उन छात्राओं के लिए फायदेमंद होगी, जो दूर–दराज के गांवों से शहरों में पढ़ने आती हैं और जिन्हें परिवहन की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। रोजगार सृजन को गति देने के लिए रोजगार मिशन समिति का गठन उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन का गठन किया है। इस मिशन के माध्यम से राज्य के युवाओं को देश के विभिन्न हिस्सों के साथ–साथ विदेशों में भी रोजगार दिलाने की दिशा में ठोस पहल की जा रही है। फूल किसानों को मंडी शुल्क से पूर्ण मुक्ति प्रदान की गई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फूलों की खेती करने वाले किसानों को बड़ी राहत दी है। सभी प्रकार के फूलों को विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद की श्रेणी से हटाकर गैर–विनिर्दिष्ट श्रेणी में रखने का निर्णय लिया है। यह निर्णय विशेष रूप से छोटे, सीमांत और फूलों की मौसमी खेती करने वाले किसानों के लिए बड़ा संबल सिद्ध होगा। SCR की तर्ज पर वाराणसी–विन्ध्य विकास प्राधिकरण का गठन उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य राजधानी क्षेत्र (SCR) की तर्ज पर काशी–विंध्य क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण (KVRDA) का गठन किया है, जिसमें वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोही सहित कुल 7 जिले शामिल हैं, जिसका उद्देश्य धार्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक विरासत और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना और कनेक्टिविटी सुधारना है। घुमंतू और विमुक्त जातियों के लिए ऐतिहासिक फैसला नट, बंजारा, बावरिया, सासी, कंजड़, कालबेलिया, सपेरा, जोगी सहित घुमंतू जातियों के लिए अलग बोर्ड गठन, कॉलोनियों और आवास की व्यवस्था तथा सभी सरकारी योजनाओं से जोड़ने का निर्णय लिया गया। पुलिस भर्ती सहित मुख्यधारा में इनकी भागीदारी सुनिश्चित हुई। त्रकृषि श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में ऐतिहासिक वृद्धि कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर 252 रुपये प्रतिदिन / 6552 रुपये प्रतिमाह की गई। इससे ग्रामीण श्रमिकों की आय और जीवन स्तर में सुधार हुआ।

एकेटीयू और नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर के बीच हुआ एमओयू

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। दोनों विश्वविद्यालय मिलकर करेंगे अनुसंधान और शोध डा0 एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय और नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर के बीच मंगलवार को गांधीनगर में माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी की उपस्थिति में माननीय कुलपति प्रोफेसर जेपी पांडे ने एमओयू पर हस्ताक्षर किया. साझेदारी के तहत दोनों विश्वविद्यालय संयुक्त रूप से शिक्षा, शोध, अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता के क्षेत्र में मिलकर काम करेंगे। फॉरेंसिक के क्षेत्र में नई तकनीकी का आदान प्रदान किया जाएगा. एकेटीयू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, थ्री डी प्रिंटिंग, नैनो टेक्नोलॉजी जैसी नई उभरती तकनीकी के जरिये सहयोग प्रदान करेगा। विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ इन तकनीकी के उपयोग में मदद करेंगे। विश्वविद्यालयों की शिक्षण, अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता गतिविधियों में सामान्य रूप से और विशेष रूप से फोरेंसिक जीवविज्ञान और सीरोलॉजी, फोरेंसिक रसायन विज्ञान और विष विज्ञान तथा संदिग्ध दस्तावेजों और फिंगरप्रिंट जांच के क्षेत्र में रुचि को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा. साथ ही शिक्षकों और छात्रों के लिए कार्यशालाएं, फैकेल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम आदि का भी आयोजन होगा। ए के टी यू नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर को इनक्यूबेशन और उद्यमिता के क्षेत्र में सहयोग देगा. इसके अलावा टीम ने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का भी भ्रमण किया. यहां स्थापित प्रयोगशालाओं सहित अन्य उपक्रमों की कार्यप्रणाली को जाना और भविष्य में संयुक्त रूप से नवाचार शोध में कार्य करने पर सहमति बनी. इस दौरान अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रोफेसर ओ पी सिंह, एसो0 डीन इनोवेशन डा0 अनुज कुमार शर्मा, हेड इन्नोवेशन हब महीप सिंह मौजूद रहे।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा SIR की तिथियां संशोधित की गई

मतदाता सूची का आलेख्य प्रकाशन 06 जनवरी 2026 को होगा
अब मतदाता सूची का अन्तिम प्रकाशन 06 मार्च, 2026 को होगा

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवदीप रिणवा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अर्हता तिथि 01 जनवरी, 2026 के आधार पर प्रदेश में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (ै प्) की घोषित तिथियों में संशोधन करते हुए नई तिथियां जारी कर दी गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि संशोधित तिथियों के अनुसार अब मतदाता सूची का आलेख्य प्रकाशन 06 जनवरी, 2026 को किया जाएगा। दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि 06 जनवरी से 06 फरवरी, 2026 तक निर्धारित की गई है। 06 जनवरी से 27 फरवरी 2026 तक नोटिस चरण, गणना प्रपत्रों पर निर्णय और दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 06 मार्च, 2026 को किया जाएगा।

पांच दिवसीय बैंकिंग के समर्थन में बैंककर्मियों ने प्रदर्शन एवं सभाएं की

सरकार के अड़ियल रुख पर देशव्यापी हड़ताल निश्चित– अनिल श्रीवास्तव

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंककर्मियों ने केंद्र सरकार द्वारा ष्पांच दिवसीय बैंकिंगष लागू न करने के विरोध में यूनियन बैंक (कपूरथला), सेंट्रल बैंक (हजरतगंज), बैंक ऑफ़ इंडिया (चौक) तथा केनरा बैंक (गोमती नगर) में जोरदार प्रदर्शन एवं सभाएं की। अनिल श्रीवास्तव, जिला संयोजक ने बताया कि इसी क्रम में फोरम द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर हर जिले में धरना, रैली एवं प्रदर्शन किया जा रहा है। फिर भी सरकार अगर अपने अड़ियल रुख पर बनी रही तो हम निश्चित ही हड़ताल पर जाएंगे। उन्होंने बताया कि आज फोरम द्वारा देशव्यापी प्रदर्शन किया गया। सभा में कामरेड वाई के अरोड़ा, लक्ष्मण सिंह, एस के संगतानी, संदीप सिंह, वी के माथुर, बी डी पाण्डेय, राकेश पाण्डेय, विभाकर कुशवाहा आदि ने कहा कि बैंक कर्मियों पर बढ़ते हुए तनाव और दबाव के चलते ष्पांच दिवसीय बैंकिंग प्रणालीष अविलंब लागू होनी चाहिए। बैंककर्मी सरकार के ढीले रवैये को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रदर्शन में काम. धनंजय सिंह, वी के श्रीवास्तव, तारकेश्वर चौहान, आकाश शर्मा, आशुतोष वर्मा के साथ ललित श्रीवास्तव, विशाखा वर्मा, दिनेश विश्वकर्मा, शकील अहमद, कीर्तिवर्धन सिंह, के एम श्रीवास्तव, मोनिका शुक्ला आदि बैंक नेताओं ने सरकार और आई.बी.ए. को आगाह करते हुए कहा कि जब अनेक सरकारी विभागों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों में ष्पांच दिवसीय कार्य प्रणाली लागू है, तो फिर बैंक कर्मियों को इससे अलग क्यों रखा जा रहा है। अनिल तिवारी (मीडिया प्रभारी) ने बताया कि आगामी 4 जनवरी को बैंक कर्मियों द्वारा ट्वीटर अभियान चलाया जाएगा और 5 जनवरी को स्टेट बैंक, मुख्य शाखा पर सुबह 11 बजे से बैंककर्मियों द्वारा धरना तथा दोपहर 2 से 3 बजे संयुक्त प्रदर्शन किया जाएगा।

ब्राह्मण विधायकों की बैठक को लेकर भाजपा विधायक ने दी सफाई, कहा- जय श्री राम, जय सनातन, जय भाजपा

संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान कुशीनगर से भाजपा विधायक पी एन पाठक के सरकारी आवास पर ब्राह्मण विधायकों की बैठक को लेकर उठे विवाद पर अब स्वयं विधायक की प्रतिक्रिया सामने आई है। सोशल मीडिया के जरिए दिए गए बयान से एक बार फिर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। भाजपा विधायक पंचानंद पाठक ने एक्स पर किए गए अपने पोस्ट में कहा कि ब्राह्मण समाज को जोड़ने का कार्य करता है, न कि विभाजन का। उन्होंने लिखा, जय श्री राम, जय सनातन, जय भाजपा। सनातन परंपरा में ब्राह्मण को समाज का मार्गदर्शक, विचारक और संतुलनकर्ता माना गया है। जहां ब्राह्मण एकत्र होता है, वहां ज्ञान, विवेक और चिंतन का मंथन होता है, जो हिंदू अस्मिता को सशक्त बनाता है। उसका धर्म समाज को जोड़ना है, विभाजन नहीं। गौरतलब है कि बीते दिनों लखनऊ में हुई इस बैठक के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया था।

पार्टी नेतृत्व ने इसे संगठनात्मक अनुशासन से जोड़ते हुए नाराजगी जाहिर की थी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने बैठक में शामिल विधायकों को नसीहत देते हुए सख्त चेतावनी भी दी थी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पंचानंद पाठक का यह बयान पार्टी अध्यक्ष की चेतावनी के बाद अपनी स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि, भाजपा की ओर से इस बयान पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।

नए साल से पहले बारिश बढ़ाएगी ठिठुरन, मौसम विभाग ने जारी किया भीषण ठंड का अलर्ट

संवाददाता

लखनऊ। भीषण ठंड और घने कोहरे की चपेट में आये उत्तर प्रदेश में नए साल से बारिश के आसार जताये गये हैं जिससे ठंड और अधिक बढ़ने की आशंका है। लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर समेत प्रदेश के 37 शहर घने कोहरे और ठंड की चपेट में हैं। मंगलवार को कई इलाकों में दृश्यता का स्तर घटकर मात्र 20 मीटर तक रह गया, जिससे सड़कों पर चलना बेहद जोखिम भरा हो गया है। कोहरे के चलते रेल और हवाई यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज समेत विभिन्न स्टेशनों से गुजरने वाली 100 से अधिक ट्रेनें 2 से 15 घंटे की देरी से चल रही हैं। वहीं 10 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। बाराबंकी और फतेहपुर प्रदेश के सबसे ठंडे जिले रहे, जहां न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले तीन दिनों के लिए भीषण ठंड का अलर्ट जारी किया है और लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने की अपील की गई है। स्थिति को देखते हुए प्रदेश सरकार भी अलर्ट मोड पर है। प्रदेश भर में स्कूल और कॉलेज 1 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। अधिकारियों को सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलाने और कंबल वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के

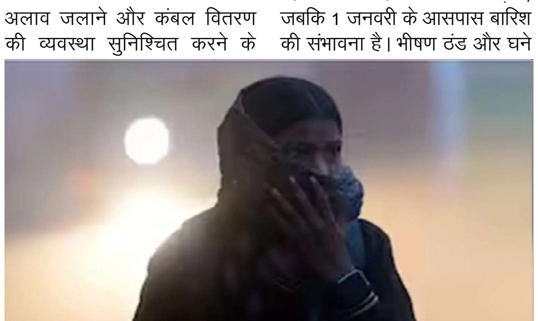

निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमजोर वर्गों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने को कहा है। सोमवार को प्रदेश के 25 से अधिक शहरों में तापमान दो से चार डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। हाथरस में कोहरे के कारण दो गंभीर सड़क हादसे हुए, जिनमें सात लोग घायल हो गए। लखनऊ स्थित मौसम वैज्ञानिक अतुल सिंह के अनुसार, पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी के कारण मैदानी क्षेत्रों में ठंड बनी हुई है। उन्होंने बताया कि अगले तीन दिनों तक दिन और रात दोनों समय ठंड बढ़ेगी, जबकि 1 जनवरी के आसपास बारिश की संभावना है। भीषण ठंड और घने कोहरे से किसानों की चिंता भी बढ़ गई है। आलू और सरसों की फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को खेतों की नियमित निगरानी करने और कीट व रोग नियंत्रण के लिए जिंक और क्लोरपायरीफॉस के छिड़काव की सलाह दी है।

संक्षिप्त

निगेटिव बैलेन्स है तो कभी भी स्वत: कट सकती है बिजली
समय से करा लें रिचार्ज, कारपोशन ने की अपील

लखनऊ ब्यूरो, लखनऊ। जिन प्रीपेड स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के अकाउंट पर नेगेटिव बैलेंस है, उन उपभोक्ताओं के विद्युत संयोजन कभी भी ऑटोमेटिक तरीके से स्वतः ही कट सकते हैं। अतः ऐसे उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि वे तत्काल अपने प्रीपेड मीटर में समुचित धनराशि का रिचार्ज करा कर अपना अकाउंट पॉजिटिव कर ले। इस समय आकर्षक ओ0टी0एस0 चल रही है उसका लाभ लेकर अपना बकाया जमा कर दे। यह जानकारी उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के निदेशक वाणिज्य प्रशांत वर्मा ने दी है।

3 साल से बजट नहीं मिला, जिला पंचायत सदस्य भूख हड़ताल पर बैठे

संवाददाता, लखनऊ। लखनऊ में जिला पंचायत अध्यक्ष और सदस्यों ने मंगलवार को विरोध प्रदर्शन किया। अधिकारियों पर अवैध वसूली और विकास कार्य न करने के आरोप लगाते हुए कैसरबाग स्थित पंचायत भवन पर भूख हड़ताल पर बैठ गए। विजय बहादुर ने कहा हम लोग लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर परेशान है। आज हमें धरने पर बैठना पड़ा। 3 साल का बजट पड़ा हुआ है ना तो कोई टेंडर हो रहा है और ना विकास का काम।

काकोरी में पानी टंकी के पास चौकीदार का शव मिला

संवाददाता

लखनऊ। काकोरी कोतवाली क्षेत्र के पलेहनदा गांव में मंगलवार को जल निगम की टंकी परिसर में एक अधेड़ व्यक्ति का शव मिला। मृतक की पहचान पलेहनदा निवासी श्यामू गौतम (45) पुत्र स्वर्गीय रामजीवन के रूप में हुई है। वह टंकी का चौकीदार था। जानकारी के अनुसार, श्यामू गौतम एक निजी ठेकेदार के माध्यम से जल निगम की टंकी पर चौकीदारी का कार्य करते थे। वह सोमवार रात को अपनी नियमित ड्यूटी पर गए थे। मंगलवार सुबह गांव के लोगों ने उन्हें मृत पाया, जिसके बाद परिजनों और पुलिस को सूचित किया गया। काकोरी पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। पुलिस प्रथम दृष्टया इस मामले को संदिग्ध मान रही है। काकोरी कोतवाली प्रभारी निरीक्षक सतीश चंद्र राठौर ने बताया।

एआई और डेटा में नवाचार के नए मापदंड स्थापित करने के लिए याद किया जाएगा साल 2025 : योगी

संवाददाता

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को वर्ष 2026 को राज्य के लिए एक अहम साल बताते हुए कहा कि वर्ष 2025 को टेक्नोलॉजी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और डेटा–संचालित नवाचार में नए मानक स्थापित करने के लिए याद किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि वे वर्ष 2026 के लिए एक विशेष संकल्प लें और अपने आसपास पांच बच्चों को कंप्यूटर और एआई के विषय में जागरूक करें। मुख्यमंत्री ने योगी की पातीश शीर्षक से पोस्ट की गई अपील में कहा, यह आंग्ल वर्ष 2026 में प्रवेश का समय है। 2025 का वर्ष टेक्नोलॉजी, एआई व डेटा में नवाचार के नए मापदंड स्थापित करने के लिए स्मरण किया जाएगा। उत्तर प्रदेश भविष्योन्मुखी विकास के नए मानक गढ़ रहा है।

प्रदेश के डिजिटल भविष्य को दिशा देने और निवेश का केंद्र बनाने में सरकार को आशातीत सफलता मिल रही है। उन्होंने अपनी चिट्ठी में आगे कहा, निवेश तभी सुरक्षित रह सकता है, जब समाज और राज्य सुरक्षित हों। प्रदेश में सुशासन के राज ने विश्व भर में ब्रांड यूपी को सशक्त किया है। उत्तर प्रदेश अब निवेशकों के विश्वास का राज्य बन गया है। आदित्यनाथ ने एआई तथा अन्य क्षेत्रों में अपनी सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा, लखनऊ और नोएडा में एआई सिटी बसाने की तैयारी है। जेवर में 3,700 करोड़ रुपये से सेमीकंडक्टर इकाई का

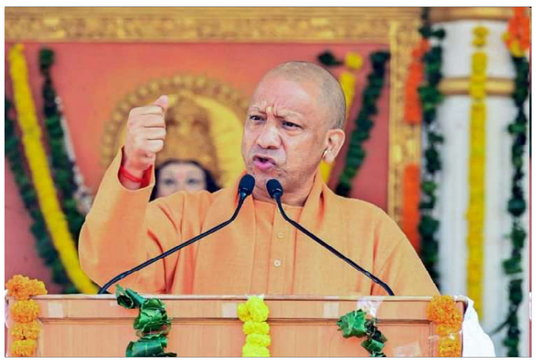

निर्माण हो रहा है। स्वदेशी सेंटर, सुरक्षित डेटा को ध्यान में रखकर बनी डेटा सेंटर नीति की सफलता दिखने लगी है। पांच हाइपरस्केल डेटा सेंटर पार्क का व्यावसायिक उपयोग प्रारंभ हो चुका है। उन्होंने कहा, डेटा सेंटर क्षेत्र में 30 हजार करोड़ के निवेश का लक्ष्य है। नौ शहरों में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किए गए हैं। ड्रोन, रोबोटिक्स और मोबाइल उत्पादन में भी हम नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। श्एआई प्रज्ञाश के माध्यम से 10 लाख नागरिकों को एआई प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हजारों नई नौकरियां सृजित हो रही हैं। मुख्यमंत्री ने युवाओं से अपील करते हुए कहा, मैं चाहूंगा कि मेरे युवा साथी वर्ष 2026 के लिए एक विशेष संकल्प लें। आप अपने आसपास पांच बच्चों को कंप्यूटर और एआई के विषय में जागरूक करें। हर सप्ताह कम से कम एक घंटा ज्ञानदान के लिए निकालें। उन्होंने कहा, सरकार और आपका प्रयास संयुक्त रूप से न केवल विकसित उत्तर प्रदेश के सपने को पूरा करेगा, अपितु उत्तर प्रदेश को विज्ञान–प्रौद्योगिकी की वैश्विक राजधानी के रूप में स्थापित करने में भी सहायक होगा।

एनजीटी सदस्य डॉ अफ़रोज़ अहमद ने माना, कन्नौज ने किया पर्यावरण पर बेहतरीन काम

बृजेश चतुर्वेदी

कन्नौज। जिला पर्यावरण समिति की एक बैठक देश के जाने माने पर्यावरणविद और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) प्रधान पीठ, के सदस्य एवं सचिव, भारत सरकार डॉ. अफ़रोज़ अहमद की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित गांधी सभागार में की गई। बैठक को संबोधित करते हुए डॉ. अफरोज अहमद ने कहा कि हरित न्यायाधिकरण द्वारा पर्यावरण सुरक्षा के उद्देश्य से सूखा एवं गीला कचरा प्रबंधन, खनन नियंत्रण, नदियों के संरक्षण, वन प्रबंधन सहित विभिन्न विषयों पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत समितियों का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि कचरा प्रबंधन की दिशा में जो भी कमियां हैं, उन्हें शीघ्र दूर किया जाएगा। कहा कि इंदौर एवं अहमदाबाद के वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का अध्ययन कर उसी तर्ज पर जिले में कार्य किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि कचरे को बिना ट्रीट किए डंप करना गंभीर समस्या का कारण बन रहा है। बायोवेस्ट कचरे का 48 घंटे के भीतर निस्तारण अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए। साथ ही उन्होंने कूड़ा संग्रहण वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगाए जाने तथा कूड़ा निस्तारण की बेहतर निगरानी किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी, चेयरमैन एवं पार्षदों के साथ बैठक कर पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रेरित करें। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) निर्माण की जिम्मेदारी जल निगम की होगी। उन्होंने निर्देशित किया कि ग्राम पंचायत स्तर पर गठित पर्यावरण समितियों में सेवानिवृत्त वन विभाग, उद्यान विभाग के कर्मचारियों, पर्यावरण संरक्षण में कार्यरत एनजीओ प्रतिनिधियों एवं बुद्धिजीवियों को सदस्य के रूप में शामिल किया जाए। कहा कि पर्यावरण संरक्षण को धरातल पर उतारने का सराहनीय कार्य कन्नौज जिला कर रहा है। उन्होंने नदियों के संरक्षण पर विशेष जोर देते हुए कहा कि नदियों का निर्माण कठिन है, अतः उन्हें संरक्षित रखना अत्यंत आवश्यक है। फूलों के संरक्षण, प्राकृतिक उत्पादों को बढ़ावा देने तथा किसानों एवं बुद्धिजीवियों को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ने पर भी उन्होंने बल दिया। डॉ अहमद ने कहा कि सीएसआर (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) की धनराशि शिक्षा, स्वास्थ्य एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण में भी व्यय की जाए। टोल प्लाजा पर टैंकरों की सघन जांच की जाए तथा खतरनाक रसायनों के सुरक्षित निस्तारण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। बैठक के दौरान ग्राम पंचायतों में कूड़ा निस्तारण एवं पांडु नदी के जीर्णोद्धार से संबंधित प्रस्तुत की गई पीपीटी को देखकर माननीय डॉ. अफरोज अहमद ने किए जा रहे कार्यों पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए माना कि कन्नौज में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में प्रशंसनीय कार्य किए जा रहे है। प्रदेश स्तर पर कन्नौज का कार्य प्रशंसनीय एवं अनुकरणीय है। आने वाले समय में शेष बचे कार्यों को भी शीघ्र पूर्ण कर पर्यावरण को और अधिक बेहतर बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पर्यावरण सभी के लिए है और यदि हम आज इसका संरक्षण नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ भी शेष नहीं रहेगा। डॉ. अफरोज अहमद ने कहा कि कन्नौज एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक नगर है, जो अपनी विशिष्ट खुशबू के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। आज इस खुशबू का अनुभव कर यह विश्वास और भी दृढ़ हुआ है कि कन्नौज में किया जा रहा उत्कृष्ट कार्य देशभर में अपनी सकारात्मक पहचान बनाएगा। उन्होंने कहा कि वे अपने आदेशों में जनपद कन्नौज के इन प्रयासों का उल्लेख अवश्य करेंगे। बैठक में जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री, पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार, अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) श्री देवेन्द्र सिंह, मुख्य विकास अधिकारी रामकृपाल चौधरी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. स्वदेश कुमार, प्रभागीय वनाधिकारी हेमंत कुमार सेठ सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

कुछ ही दिन में उखड़ गयी 20 लाख की लागत से बनी सड़क

बृजेश चतुर्वेदी

कन्नौज। छिबरामऊ में हाल ही में बनी एक सड़क निर्माण के कुछ ही दिनों बाद उखड़ने लगी है। 20 लाख रुपये की लागत से बनी इस सड़क के घटिया निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने नाराजगी व्यक्त की है और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए दोबारा मजबूत सड़क बनाने की मांग की है। यह मामला छिबरामऊ क्षेत्र का है, जहां सलेमपुर के पास जीटी रोड से रतनपुर, हयातनगर होते हुए चंद्रपुर गांव तक 2400 मीटर लंबी सड़क का निर्माण कराया गया था। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क निर्माण में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया है, जिसका खामियाजा स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ रहा है। गांव के एक निवासी ने बताया कि उन्होंने सड़क निर्माण के दौरान ही ठेकेदार को घटिया सामग्री के इस्तेमाल से रोका था, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। निर्माण पूरा होने के तीसरे दिन से ही सड़क टूटने लगी थी। अब भुगतान कराने से पहले गड्ढों को पैचवर्क के जरिए भरा जा रहा है, जिससे वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। सड़क उखड़ती देख कई ग्रामीण मौके पर एकत्र हुए और उन्होंने हाथ से सड़क उखाड़ते हुए वीडियो भी बनाए। कन्नौज में संपर्क मार्गों के निर्माण में धांधली का यह कोई पहला मामला नहीं है। जिले में ऐसी दर्जनों सड़कें हैं जो बनते ही उखड़ने लगीं और उनमें भ्रष्टाचार के आरोप लगे। यह स्थिति तब है जब जिले की तीनों विधानसभा सीटों पर भाजपा के विधायक हैं, जिनमें सदर विधायक असीम अरुण सरकार में समाज कल्याण मंत्री भी हैं। इसके बावजूद सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को कथित तौर पर दरकिनार किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ की प्रमुख नृत्य एवं लोक कला, संस्कृति पर केंद्रित फोटो प्रदर्शनी

फोटो प्रदर्शनी 02 जनवरी से 04 जनवरी 2026 तक

बीएनई

रायपुर। छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक-संस्कृति, पारंपरिक नृत्यों और विविध लोक कलाओं को व्यापक जनसमुदाय तक पहुँचाने के उद्देश्य से क्लाउड एवं संस्कृति विभाग, छत्तीसगढ़ के सहयोग से एक विशेष फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रदर्शनी राज्य की जनजातीय, ग्रामीण और लोक परंपराओं की जीवंत, कलात्मक और प्रामाणिक झलक प्रस्तुत करेगी, जो छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान को सशक्त रूप से दर्शाती है। यह फोटो प्रदर्शनी 02 जनवरी से 04 जनवरी 2026 तक कला वीथिका, महंत घासीदास परिसर, घड़ी चौक, रायपुर में आयोजित की जाएगी। प्रदर्शनी प्रतिदिन प्रातः 11 बजे से सायं 7 बजे तक खुली रहेगी। प्रदर्शनी में प्रवेश सभी के लिए पूर्णतः निःशुल्क रहेगा, जिससे अधिक से अधिक लोग इस सांस्कृतिक आयोजन से जुड़ सकें। फोटो प्रदर्शनी छायाचित्रों के माध्यम से न केवल दृश्य सौंदर्य प्रस्तुत करेगी, बल्कि छत्तीसगढ़ के लोक जीवन, सांस्कृतिक विविधता और परंपराओं के संरक्षण का संदेश भी देगी। प्रदर्शनी का उद्देश्य नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ना, लोक कलाकारों और शिल्पकारों के योगदान को रेखांकित करना तथा लोक कला के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाना है। यह आयोजन कला प्रेमियों के साथ-साथ विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं, संस्कृति अध्येताओं और आम नागरिकों के लिए भी छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत को जानने, समझने और अनुभव करने का एक महत्वपूर्ण अवसर सिद्ध होगा। इस फोटो प्रदर्शनी में दीपेन्द्र दीवान, अखिलेश, हर्षा, धनेश्वर और सूर्या दीवान की फोटोग्राफी प्रदर्शनी में देखने को मिलेगा।

संक्षिप्त

भारत के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेअर अर्थ भंडार, जानिए फिर भी क्यों उत्पादन में पीछे

एजेंसी

नई दिल्ली। रेअर अर्थ अयस्क भंडार के मामले में भारत इस समय तीसरे स्थान पर है। हालांकि, इसका उत्पादन प्रमुख वैश्विक देशों की तुलना में सबसे कम है, जो संसाधन उपलब्धता और वास्तविक उत्पादन के बीच भारी अंतर को दर्शाता है। आंकड़ों से पता चला है कि भारत के पास लगभग 69 लाख टन रेअर अर्थ ऑक्साइड (आरईओ) भंडार है। इससे पहले चीन और ब्राजील हैं। एमिकस के आंकड़ों के अनुसार, चीन के पास 4.4 करोड़ टन भंडार है। ब्राजील के पास 2.1 करोड़ टन का भंडार है। ऑस्ट्रेलिया (57 लाख टन), रूस (38 लाख टन), वियतनाम (35 लाख टन) और अमेरिका (19 लाख टन) शामिल हैं। अपने मजबूत भंडार के बावजूद भारत का उत्पादन सीमित है। 2024 में भारत ने केवल 2,900 टन दुर्लभ धातुओं का उत्पादन किया, जो वैश्विक स्तर पर सातवें स्थान पर रहा। चीन ने 2.7 लाख टन का उत्पादन किया, जिससे वह वैश्विक स्तर पर अग्रणी बन गया।

उत्पादन लक्ष्य चूक पर सरकार सख्त, रिलायंस-बीपी को भरना होगा 30 अरब डॉलर से अधिक का मुआवजा

एजेंसी

नई दिल्ली। केंद्र ने कृष्णा-गोदावरी बेसिन के केजी-डी6 गैस क्षेत्र से प्राकृतिक गैस उत्पादन का लक्ष्य पूरा नहीं करने के मामले में रिलायंस इंडस्ट्रीज और उसकी साझेदार बीपी से 30 अरब डॉलर से अधिक का मुआवजा मांगा है। सूत्रों के मुताबिक, सरकार ने यह दावा तीन-सदस्यीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण के समक्ष पेश किया है। 14 साल पुराने इस मामले पर सुनवाई 7 नवंबर को पूरी हो चुकी है। न्यायाधिकरण अगले वर्ष किसी भी समय फैसला सुना सकता है। उधर, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इस रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा, 30 अरब डॉलर का कोई दावा नहीं है। केजी-डी6 ब्लॉक के संबंध में भारत सरकार का दावा 24.7 करोड़ डॉलर का है, जिसका खुलासा उचित और लगातार किया गया है। अधिक सुविधाएं विकसित करने का आरोप सरकार का आरोप है कि दोनों साझेदारों ने केजी-डी6 ब्लॉक में जरूरत से ज्यादा बड़ी सुविधाएं विकसित कीं, लेकिन प्राकृतिक गैस उत्पादन के निर्धारित लक्ष्यों को पाने में नाकाम रहे। मध्यस्थता प्रक्रिया में सरकार ने उत्पादित नहीं की जा सकी गैस का मौद्रिक मूल्य मांगने के साथ अतिरिक्त खर्च, ईंधन विपणन और ब्याज पर भी मुआवजा मांगा है। इन दावों का कुल मूल्य 30 अरब डॉलर से अधिक है। उत्पादन दोगुना करने के बजाय घटाया रिलायंस ने 2.47 अरब डॉलर के निवेश से प्रतिदिन चार करोड़ मानक घन मीटर गैस उत्पादन का लक्ष्य रखा था। 2006 में इसे 8.18 अरब डॉलर का निवेश और मार्च, 2011 तक 31 कुओं की ड्रिलिंग के साथ उत्पादन दोगुना करने का अनुमान जताया गया। कंपनी 22 कुएं ही खोद सकी, जिनमें 18 से ही उत्पादन शुरू हो पाया। बाद में गैस भंडार का अनुमान 10.03 लाख करोड़ से घटाकर 3.10 लाख करोड़ घनफुट किया गया। सरकार ने इसके लिए रिलायंस-बीपी को जिम्मेदार ठहराते हुए शुरुआती वर्षों में किए 3.02 अरब डॉलर के खर्च को लागत वसूली गणना से बाहर कर दिया। रिलायंस ने इसके विरोध में 2011 में मध्यस्थता नोटिस दिया था। जनवरी, 2023 के बाद सुनवाई शुरू हुई थी। यह है विवाद की जड़ इस विवाद की जड़ केजी-डी6 ब्लॉक के धीरूभाई-1 और धीरूभाई-3 (डी1 एवं डी3) गैस क्षेत्रों से जुड़ी है। सरकार का कहना है कि रिलायंस ने स्वीकृत निवेश योजना का पालन नहीं किया, जिससे उत्पादन क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो सका। डी1 और डी3 क्षेत्रों में उत्पादन 2010 में शुरू हुआ था, लेकिन उसके एक साल बाद से ही उत्पादन अनुमानों से पीछे रहने लगा। फरवरी, 2020 में दोनों गैस क्षेत्र अपने अनुमानित जीवनकाल से काफी पहले बंद हो गए।

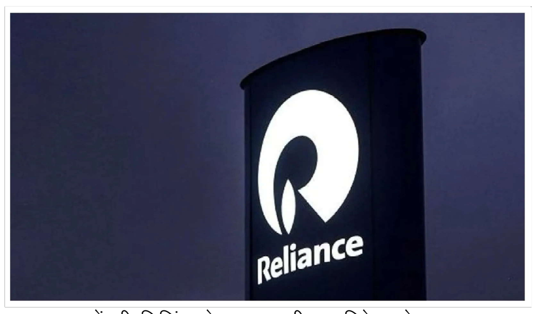

कड़ाके की ठंड में जरूरतमंदों को राहत पहुंचाने हेतु एनसीएल ने की सराहनीय पहल

सीएसआर अंतर्गत चितरंगी, बरगवा एवं आसपास के क्षेत्रों में किया कंबल वितरण

बीएनई

सिंगरौली। नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) ने अपनी निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पहल के तहत सिंगरौली एवं सोनभद्र क्षेत्र में शीतलहर के बीच गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों में लगातार कंबल वितरण का कार्य कर रही है। इस क्रम में कंपनी ने सोमवार को दार पंचायत, चितरंगी जो कि एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है, में 200 कंबलों का वितरण किया। इस अवसर पर सीधी-सिंगरौली के माननीय सांसद डा. राजेश मिश्रा, माननीया राज्यमंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन एवं चितरंगी विधायक, राधा सिंह, पंचायत प्रतिनिधिगण तथा एनसीएल के महाप्रबंधक (सीएसआर) राजीव रंजन विशेष रूप से उपस्थित रहे। इसी प्रकार, सांसद डॉ. राजेश मिश्रा एवं माननीय देवसर विधायक श्री राजेन्द्र मेश्राम की गरिमामयी उपस्थिति में बरगवा के अम्बेडकर वार्ड एवं तिलक वार्ड (नगर परिषद) में भी 200 कंबलों का वितरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान जनप्रतिनिधिगणों ने एनसीएल की इस मानवीय पहल की प्रशंसा की तथा इसे स्थानीय समाज के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता का प्रतीक बताया। गौरतलब है कि एनसीएल ने इन कंबलों की खरीद खादी ग्रामोद्योग से की है, जिससे न केवल जरूरतमंदों को ठंड से बचाव सुनिश्चित हो रहा है, अपितु स्थानीय हस्तशिल्प को बढ़ावा भी मिल रहा है।

पीडीएस के तहत छत्तीसगढ़ में 2.73 करोड़ लोग को खाद्यान्न सुरक्षा

राशन कार्डों का 85 प्रतिशत सदस्यों का ई-केवायसी पूर्ण
राज्य के सभी उचित मूल्य दुकानों में ई-केवायसी की सुविधा उपलब्ध
''मेरा ई-केवायसी'' एप्प के माध्यम से घर बैठे कर सकते हैं केवायसी

बीएनई

रायपुर। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 82.18 लाख राशन कार्ड प्रचलित है। इन राशन कार्डों में पंजीकृत सदसस्यों की संख्या 2.73 करोड़ है। केन्द्र सरकार के निर्देश पर राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के वास्तविक हितग्राहियों को योजना का लाभ दिलाने के उददेश्य से ई-केवायसी का कार्य निरंतर जारी है। अब तक कुल पंजीकृत सदस्यों का 2.3 करोड़ याने 85 प्रतिशत सदस्यों का ई-केवायसी का काम पूर्ण हो चुका है। वास्तविक रूप से लगभग 30.32 लाख सदस्यों का ई-केवायसी हेतु शेष है। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने आज यहां बताया कि राज्य के सभी शासकीय उचित मूल्य के दुकानों में संचालित ई-पास मशीन में ई-केवायसी की सुविधा उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा जारी ''मेरा ई-केवायसी'' एप्प के माध्यम से भी ई-केवायसी किए जा सकते हैं। एप्प के माध्यम से ई-केवायसी करने हेतु एंड्रायड मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर से एप्प डाउनलोड कर हितग्राही अपना आधार नंबर डालकर आधार ओटीपी के माध्यम से फेस ई-केवायसी कर सकते हैं। अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में 14,040 शासकीय उचित मूल्य की दुकानें संचालित हो रही हैं और पंजीकृत राशन कार्डधारियों द्वारा अपनी पसंद के उचित मूल्य की दुकानों से राशन प्राप्त कर रहे हैं। वर्ष 2025 की अनुमानित जनसंख्या के अनुसार 89 प्रतिशत जनसंख्या का कव्हरेज हो रहा है। राशन वितरण को पारदर्शी बनाने के लिए आधार सिडिंग का कार्य भी किया जा रहा है। जिसके तहत् 99.7 प्रतिशत सदस्यों का आधार सीडिंग हो चुका है और 85 प्रतिशत ई-केवाईसी भी पूर्ण कर लिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि लगभग 2.73 करोड़ खाद्यान्न सुरक्षा के दायरे में आ चुके हैं, इन्हें नियमित रूप से खाद्यान्न सामग्री उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से वितरित की जा रही है। इनमें प्राथमिकता में शामिल 73 लाख से अधिक परिवारों को निःशुल्क तथा साढ़े आठ लाख गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवारों को रियायती दर पर चावल उपलब्ध कराया जा रहा है। प्राथमिकता वाले परिवारों को आयरन फोलिक एसिड तथा विटामिन बी-12 युक्त फोर्टिफाइड चावल वितरित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार की महत्वकांक्षी नियद नेल्लानार योजना के तहत् बस्तर संभाग के 5 जिले बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर एवं कांकेर के चयनित दूरस्त 402 ग्रामों के कुल 42,220 राशन कार्डधारियों को खाद्यान्न, चना, शक्कर, नमक व गुड़ का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है।

बिहार में प्रतिभा की कमी नहीं, खिलाड़ीकी क्षमता अंतरराष्ट्रीय स्तर की, बोलीं साइना नेहवाल

एजेंसी

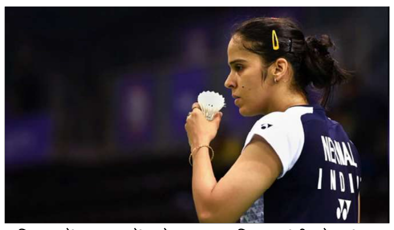

पटना। दिग्गज भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने सोमवार को कहा कि बिहार में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है और बेहतर प्रशिक्षण के जरिए यहां से भी अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार किए जा सकते हैं। साइना ने कहा कि राज्य में आधारभूत संसाधन मौजूद हैं और सही मार्गदर्शन से खिलाड़ी वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बना सकते हैं। साइना ने पाटलिपुत्र खेल परिसर में पत्रकारों को बताया कि बिहार के प्रतिभावान बैडमिंटन खिलाड़ियों का चयन कर उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने बिहार में खेलों के विकास, विशेषकर बैडमिंटन की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की। इससे पहले साइना ने बिहार की खेल मंत्री श्रेयसी सिंह से मुलाकात की। इस अवसर पर खेल मंत्री ने अंगवस्त्र और प्रतीक चिह्न भेंट कर उनका अभिनंदन किया। साइना ने कहा कि बिहार खेल के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के आयोजन के जरिए पहले ही वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना चुका है। साइना ने कहा, श्मैंने अपनी पहली राष्ट्रीय चौंपियनशिप पटना में ही जीती थी इसलिए बिहार से मेरा गहरा भावनात्मक जुड़ाव है। साइना ने कहा कि बिहार के खिलाड़ियों के विकास के लिए वह हर संभव सहयोग देने को तैयार हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि सरकार की सकारात्मक खेल नीति, खेल विभाग और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के कुशल मार्गदर्शन से आने वाले समय में राज्य से अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी निकलेंगे। उल्लेखनीय है कि साइना नेहवाल पद्मश्री, पद्म भूषण और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित हैं। वह ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। उन्होंने लंदन ओलंपिक 2012 में कांस्य पदक जीता था और विश्व नंबर एक रैंकिंग हासिल करने वाली एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी भी रही हैं।

CSK के इस नए ऑलराउंडर को विजय हजारे में पड़ी खूब मार, 10 ओवर में लुटाए 123 रन; बनाया शर्मनाक रिकॉर्ड

एजेंसी, नई दिल्ली। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में एक ऐसा रिकॉर्ड दर्ज हुआ, जिसे कोई भी गेंदबाज अपने नाम नहीं करना चाहेगा। पुद्दुचेरी के कप्तान और ऑलराउंडर अमान खान ने झारखंड के खिलाफ मुकाबले में अपने 10 ओवर के स्पेल में 123 रन लुटा दिए। इसके साथ ही उन्होंने लिस्ट-ए क्रिकेट इतिहास का सबसे महंगा स्पेल डालने का अनचाहा रिकॉर्ड बना दिया। पिछला रिकॉर्ड भी टूटा अमान खान के आंकड़ों ने पिछले सप्ताह बना रिकॉर्ड भी पीछे छोड़ दिया। इससे पहले अरुणाचल प्रदेश के मिबोम मोसू ने बिहार के खिलाफ नौ ओवर में 116 रन दिए थे। अमान का 0/123 का आंकड़ा अब लिस्ट-ए क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन लुटाने वाले स्पेल के तौर पर दर्ज हो गया है। आईपीएल 2026 में CSK ने जताया भरोसा दिलचस्प बात यह है।

12 वर्षों में कितना बदले दिलजीत दोसांझ, सोनम बाजवा ने बॉर्डर 2 के एक्टर के बारे में रखी राय

एजेंसी

फिल्म बॉर्डर 2 23 जनवरी 2026 को रिलीज होने वाली है। लगभग 30 वर्षों के बाद सनी देओल बॉर्डर की कहानी को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। फिल्म में सोनम बाजवा और दिलजीत दोसांझ जैसे नए कलाकार भी नजर आने वाले हैं। दोनों ने लोगों का ध्यान खींचा है। ऐसे में सोनम बाजवा ने दिलजीत दोसांझ के बारे में अपनी राय रखी है। 12 वर्षों में नहीं बदले दिलजीत न्यूज 18 से बातचीत में सोनम बाजवा ने दिलजीत दोसांझ के साथ काम करने का अपना अनुभव बताया है। उन्होंने बताया कि वह उन्हें 12 वर्षों से जानती हैं। इतने वर्षों में उनमें बदलाव नहीं हुआ। सोनम बाजवा ने कहा पूरी दुनिया में मशहूर होने के बावजूद वह उसी तरह के आदमी हैं जैसे पहले थे। उनका सफर प्रेरणा देने वाला है। सोनम को दिलजीत पर गर्व है सोनम बाजवा ने आगे कहा वह म्यूजिक के दीवाने हैं। वह संगीत में सांस लेते हैं। दूसरों की तरह मैं भी उनके सफर पर गर्व करती हूं। मैं उनके लिए अच्छा महसूस कर रही हूं। उन्होंने हम में से किसी को भी यह नहीं महसूस कराया कि वह ग्लोबल संसेशन हैं। वह अभी भी जमीन से जुड़े हैं और बहुत मजाकिया हैं। धुरंधर के कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने किया श्इक्कीसश का रिव्यू, धर्मेंद्र को लेकर कह दी ये बात दिलजीत के साथ सहज होने में वक्त लगा सोनम बाजवा ने खुलासा किया कि दोनों को एक दूसरे के साथ सहज होने में वक्त लगा। उन्होंने कहा शफिल्म श्पंजाब 1984श के दौरान वह उन्हें उतना नहीं जानती थीं। हालांकि श्सुपर सिंहश के दौरान चीजें बदली। दिलजीत ने इसमें सुपरहीरो का किरदार निभाया था। फिल्म में हमने बहुत मस्ती-मजाक किया। हम सेट पर बहुत कुछ अच्छा करते थे। सोनम ने कहा श्बॉर्डर 2 में एक सीन है... हमने उसे फिल्माने से पहले ज्यादा बातचीत नहीं की थी, लेकिन शूटिंग के दौरान हम इतना हंसे कि क्या बताएं। बॉर्डर 2 की स्टारकास्ट फिल्म बॉर्डर 2 में सनी देओल के साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी जैसे कलाकार हैं। यह फिल्म 1997 में आई फिल्म बॉर्डर की सीक्वल है। हाल ही में इस फिल्म का टीजर रिलीज हुआ है।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक **धर्मेन्द्र सिंह** द्वारा शौर्य प्रिंटर्स, शिवपुरी कालोनी, निकट बांसमण्डी चौराहा, लखनऊ से मुद्रित तथा एमआईजी-47, सेक्टर-ई, अलीगंज, लखनऊ (उ.प्र.) से प्रकाशित
सम्पादक-अंजू सिंह (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा) Email-lkojunction@gmail.com. RNI NO.-UPHIN/2015/64743